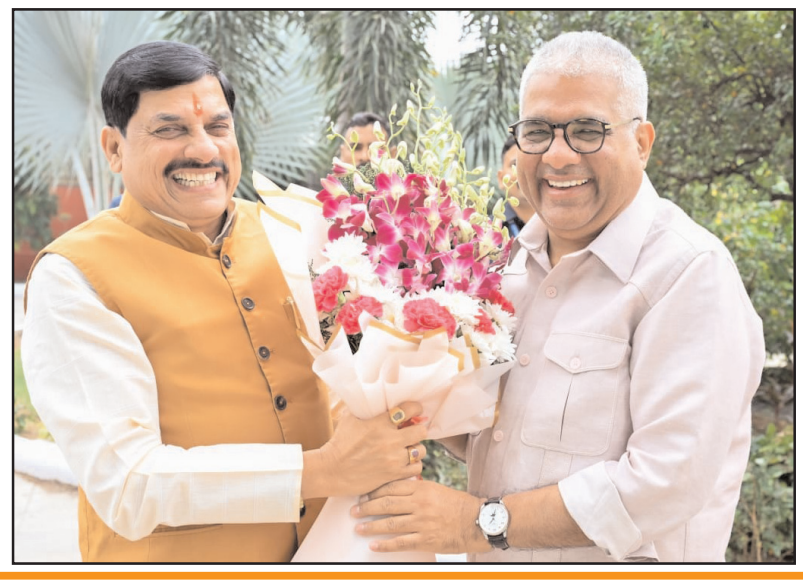
दैनिक
सच्चे दिन

वर्ष-06 | अंक-206 | प्रात:कालीन हिन्दी दैनिक | भोपाल, शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य-1 रुपये

नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री श्री यादव से की सौजन्य भेंट

मध्यप्रदेश के विकास एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर की चर्चा



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। मध्यप्रदेश प्राकृतिक संपदा, समृद्ध वन संपदा और जैव-विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्रों के संवर्धन, वन्य जीवों के संरक्षण तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

बसों में शहर-गांव का सफर सुविधाजनक बना रही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

मध्यप्रदेश सरकार आम लोगों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती बस परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश परिवहन विज़न 2030-31 के तहत शहरों से लेकर गांवों तक बस सेवाओं का विस्तार करने, यात्रियों को निर्धारित समय पर बस उपलब्ध कराने, डिजिटल और मोबाइल ऐप आधारित टिकिट व्यवस्था लागू करने और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य लोगों की यात्रा को आसान बनाना और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। यात्री परिवहन विज़न समिट-2026 की अनुशंसाओं के अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत हो चुकी है।

एक बहन ने बेटे के साथ तो दूसरी ने तीन बच्चों संग कुएं में लगाई छलांग, छह मौतों

शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी में बुधवार को दो बहनों ने अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। पहले छोटी बहन अंजलि (35) ने अपने छह साल के बेटे प्रशांत के साथ कुएं में छलांग लगाई। करीब पांच घंटे बाद बड़ी बहन सीता रावत (40) अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में मिली।दोनों घटनाओं में दो बहनों और चार बच्चों की मौत हो गई। अंजलि आठ महीने की गर्भवती थी। परिजन सीता की मौत को छोटी बहन की मौत के सदमे से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस दोनों मामलों की अलग-अलग जांच कर रही है।



बड़ी बेटी ने दो बहनों की बचा ली जान

बुधवार दोपहर करीब एक बजे बैराड़ थाना क्षेत्र के गूंगरगांव में अंजलि ने अपने छह साल के बेटे प्रशांत के साथ कुएं में छलांग लगा दी। उसकी तीन बेटियां भी साथ थीं, लेकिन बड़ी बेटी मोनिका ने खुद और अपनी दोनों छोटी बहनों को बचा लिया। इसके बाद उसने घर पहुंचकर परिजन को घटना की जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे और अंजलि व प्रशांत को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।

भोजशाला विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगे दस्तावेज

मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया था नियमित पूजा का अधिकार

धार। धार के भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 29 अक्टूबर को सुनवाई की। सभी पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए



चार सप्ताह का समय दिया है।न्यायमूर्ति संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ ने हाईकोर्ट का रिकॉर्ड भी सभी पक्षों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के 15 मई 2026 के फैसले के खिलाफ पांच याचिकाएं दायर की हैं।हाईकोर्ट ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर मानते हुए हिंदू समाज को नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार दिया था।

नमाज के लिए तय है अलग जगह

सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मुस्लिम समाज को शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की व्यवस्था देने का निर्देश दिया था। बाद में भोजशाला के पीछे दाईं ओर स्थित खसरा नंबर 612 की जमीन पर नमाज तय की गई।

चार सप्ताह में पेश होंगे दस्तावेज

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष और याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि संगठन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे चार प्रकरणों में पक्ष रख रहा है।

डिजिटल धोखाधड़ी

बैंक चूके तो करनी होगी पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई

नई दिल्ली। डिजिटल गिरफ्तारी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बैंकों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इस बीच, व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अब तक 9,400 संदिग्ध खातों को प्रतिबंधित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी संशोधन निर्देशों की जांच करने की बात कही है। ये निर्देश 31 दिसंबर तक लागू किए जाने हैं। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होने पर बैंकों का ग्राहकों के प्रति कर्तव्य है। उन्हें असामान्य लेनदेन के बारे में पड़ोसी पुलिस थानों को तुरंत सूचित करना चाहिए। यह कदम डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।



अदालत ने अपन

शीर्ष अदा
बैंकों द्वारा
विफलता के
डिजिटल धो
पड़ता है, तो
नुकसान की पू
न्यायाधीश (सीजे
जोयमाल्या बागची औ
पीठ ने एक स्वत: संज्ञान
कहा कि वित्तीय संस्थानों
कर्तव्य है कि वे अपने
कवच की तरह काम करें
सीनियर एडवोकेट एनएस
कि लगातार कोशिशों के
हाल की एक घटना का जि
को 2.5 करोड़ का नुकस

ट्रांसजेंडर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का

कोलकाता- प्रेम संबंध का मामला

बेटे-पिता समेत 3 लोगों को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया



कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बेहाला इलाके में प्रेम संबंध को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती के परिवार वालों ने एक युवक, उसके पिता और दोस्त के साथ मारपीट की। इसके बाद तीनों के पूरे कपड़े उतारकर इलाके में घुमाया गया। पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार को सरसुना थाना क्षेत्र के बसुंधरा पार्क में हुई। युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध था। आरोप है कि युवती के परिवार वालों ने दोनों को साथ देखकर युवक और उसके दोस्त को पकड़ लिया। इसके बाद युवक को एक कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में युवती के पिता और मामा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना का कथित वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। नाराज स्थानीय लोगों ने युवती के घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के पहुंचने से पहले युवती के परिवार के कुछ सदस्य वहां से फरार हो गए। वहीं, स्थानीय लोगों ने युवती के मामा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

राहत | कुछ 90% तक हुई सस्ती, 9 नवंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा यह आदेश

कैंसर की 543 दवाओं के दाम बदले

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत में दवाओं की कीमतों पर नजर रखने वाली संस्था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने कैंसर की 543 दवा की कीमतों (एमआरपी) में बदलाव किया है। यह आदेश 9 नवंबर 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। कुछ दवाओं की कीमतों में 90 प्रतिशत से ज्यादा की कमी हुई है, हालांकि, इस राहत के बावजूद कैंसर की कुछ बेहद महंगी दवाओं के दाम में बदलाव नहीं हुआ है।

एनपीपीए ने दवाओं की जो नई कीमत तय की है उसमें ब्रेस्ट कैंसर के कुछ मरीजों को दी जाने वाली दवा पाल्बोसिक्लिब के एक ब्रांड और पैक की कीमत 40,421 रुपये से घटाकर 2,720 रुपये कर दी गई है। इसी तरह कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवा थायोटेप की एक शीशी की कीमत करीब 80,072 रुपये से घटकर 7,150 रुपये हो गई है। इसके अलावा डासैटिनिब, लेंवाटिनिब और ओलापैरिब जैसी दवाओं की कीमतों में भी बड़ी कटौती की गई है, लेकिन कैंसर की कुछ दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में कटौती के बावजूद कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेहद महंगी दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनमें इम्यूनोथेरेपी की दवा कीटूडा भी शामिल है। कीटूडा का इस्तेमाल 21 से ज्यादा तरह के कैंसर के इलाज में होता है। अभी भी इसकी कीमत 2,16,500 रुपये ही बनी हुई है. ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रिबोसाइक्लिब की कीमत भी 24,435 रुपये पर ही स्थिर है। (शेष पेज 8 पर)



कीटूडा जैसी महंगी दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इस दवाई का 21 से ज्यादा तरह के कैंसर के इलाज में होता है उपयोग

क्यों कम नहीं हुई कुछ दवाओं की कीमत

मरीजों के हितों की वकालत करने वाले समूह ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क (एआईडीएएन) से जुड़ीं मालिनी ऐसोला ने इस बारे में बताया है। वह कहती हैं कि पेटेंट वाली दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव न आने का एक कारण यह है कि सरकार ने बहुत सोच-समझकर उन दवाओं को इसमें शामिल नहीं किया है, जो पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम (पीएपी) के तहत मुफ्त में दी जाती हैं। पीएपी के तहत, दवा कंपनियां प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं मुफ्त या भारी छूट पर उपलब्ध कराती हैं। उदाहरण के लिए, कैंसर के मरीजों को दो शीशियों का भुगतान करने पर तीसरी शीशी मुफ्त दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम पीएपी को बाहर रखे जाने के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे अस्पतालों और बिचौलियों को भारी मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है। ऐसोला ने यह भी बताया कि कई मामलों में कीमतों में की गई भारी कटौती एक ऐसे उदार फॉर्मूले के तहत है, जो अस्पताल या वितरक को अभी भी 42.8 प्रतिशत का मुनाफा देता है।

चक्रवात अ

राजस्थान सहित 15 राज्यों में बारिश, ठंड बढ़ेगा

चेन्नई, एजेंसी

बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। चक्रवात का असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में कल रात से बारिश का दौर शुरू हो गया है। यह अगले दो दिनों तक जारी रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के सतना, कटनी और छतरपुर समेत कई जिलों में बुधवार को बारिश हुई। राजस्थान के भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। मौसम में बदलाव के कारण जयपुर, पिलानी, सीकर, बाड़मेर और चूरू समेत लगभग सभी शहरों के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। सीकर में रात का तापमान 10.5 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं, चक्रवात के असर को देखते हुए छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में गुरुवार को स्कूल बंद रखने के आदेश हैं। ओडिशा में भी 16 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्य में करीब 30 हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। चक्रवात अर्नब मंगलवार देर रात करीब 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई।

छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में आज स्कूल बंद



राजस्थान: 27 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

राजस्थान के 27 जिलों में गुरुवार को तेज बारिश का अलर्ट है। बुधवार देर शाम भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में बादल छाए और देर रात हल्की बारिश हुई। मौसम में बदलाव से ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, पिलानी, सीकर, बाड़मेर और चूरू समेत लगभग सभी शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीकर और फतेहपुर में रात का तापमान गिरकर 10 डिग्री तक पहुंच गया।

मध्य प्रदेश: भोपाल-ग्वालियर समेत 12 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट

चक्रवात अर्नब के असर से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को सतना, कटनी और छतरपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। गुरुवार को इसका असर और बढ़ने की संभावना है। मौसम केंद्र ने भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, हरदा, ग्वालियर सहित 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भावुक पल | रिलायंस के बाद मार्केट कैप के हिसाब से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी जियो

अनंत की स्पीच सुनकर मुकेश अंबानी के छलके आंसू

नई दिल्ली (एजेंसी)

जियो प्लेटफॉर्म्स की आईपीओ लिस्टिंग सेरेमनी में एक ऐसा पल आया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने बच्चों अनंत, आकाश और ईशा का संबोधन सुनकर भावुक हो गए। खासकर अनंत की स्पीच के दौरान मुकेश अंबानी की आंखें डबडबाई गईं।



यह पल सिर्फ कारोबारी उपलब्धि का नहीं, बल्कि अंबानी परिवार के सफर, पुरानी यादों व नई पीढ़ी की जिम्मेदारियों का भी था। 28 अक्टूबर 2026 को आयोजित समारोह में ईशा, अनंत और आकाश अंबानी ने जियो की 10 साल की यात्रा, ग्राहकों के भरोसे और रिलायंस की विरासत पर बात की।



अनंत बोले, एक्सचेंज की घंटी मेरे लिए मंदिर की घंटी जैसी

अनंत अंबानी ने अपने संबोधन की शुरुआत आभार जताने के साथ की। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा मायने रखने वाला शब्द कृतज्ञता है। अनंत ने उन लाखों लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने जियो पर भरोसा किया और इस दिन को संभव बनाया। अनंत अंबानी ने आईपीओ लिस्टिंग के दौरान बजने वाली एक्सचेंज की घंटी की तुलना मंदिर की घंटी से की। उन्होंने कहा, मेरे लिए कारोबार पूजा है और हर पूजा प्रसाद के साथ पूरी होती है।

ईशा ने याद दिलाए पिता के पुराने दिन

रिलायंस रिटेल वेंचर्स की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने अपने संबोधन में परिवार की पुरानी यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि कुछ शाम पहले डिनर टेबल पर मुकेश अंबानी 1977 के दिनों को याद कर रहे थे। उस समय वह महज 20 साल के थे और रिलायंस की पहली पब्लिक ऑफरिंग पर काम कर रहे थे। ईशा ने कहा कि उनके दादा धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को आम लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया था। उनकी यह बात रिलायंस की उस विरासत की याद दिलाती है, जिसने कंपनी के सफर की नींव रखी। ईशा अंबानी ने जियो की कारोबारी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि इस साल कंपनी का रेवेन्यू करीब 15.5 अरब डॉलर रहा, जबकि उसकी वास्तविक कमाई करीब 8 अरब डॉलर रही।

प्रयागराज में नीले ड्रम में मिले 5 रूपये करोड़ कैश

जमीन में गाड़ी थी गड्डियां; पुलिस पड़ोसी से झगड़े की जांच करने पहुंची तो राज खुला

प्रयागराज। प्रयागराज में नीले ड्रम में 5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। 500-500 रुपए की गड्डियां कपड़े में लपेटी गईं और इन्हें जमीन में गाड़कर रखा गया था। मामला प्रयागराज से 32 किमी दूर बरईपुर गांव में राकेश यादव के घर का है। बुधवार रात को पुलिस ने रकम बरामद की। 5-6 दिन पहले राकेश का पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था।

राकेश के खिलाफ दर्ज हुई। पुलिस पहुंची तो राकेश की दरोगा से बहस हो गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो घर के अंदर करोड़ों रुपए छिपाने की कहानी सामने आई।

पुलिस ने गांव की बिजली काटकर मारी रेड

नवाबगंज इलाके के बरईपुर गांव में राकेश यादव उर्फ महाकाल का पुश्तैनी मकान है। पुलिस को राकेश के घर में चोरी के रुपए जमीन में गाड़कर रखने का इनपुट मिला था। यह बात पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया तक पहुंची।

साढ़े 4 घंटे तक चला सर्च अभियान

पुलिस के मुताबिक, घर की तलाशी के दौरान जमीन में दबाकर रखे गए 3 नीले ड्रम मिले। इसमें कपड़े से लपेटकर नोटों की गड्डियां रखी गई थीं।

किसानों की आय बढाने के लिए उद्यानिकी फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित करें -कृषि उत्पादन आयुक्त श्री गुप्ता

उज्जैन । रबी फसल की प्लानिंग एवं खरीफ फसल की संभागीय समीक्षा बैठक आज कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के प्रथम सत्र में सहकारिता, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग के काम-काज की समीक्षा करते हुए आगामी प्लानिंग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा है कि उज्जैन संभाग में ऐसे किसान जो सहकारी बैंक या समिति के कर्मचारियों की गलतियों के कारण डिफाल्टर हुए है उनके लिए सहकारित विभाग द्वारा संचालित की जा रही कवच योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को दिलवाये। साथ ही उन्होंने किसानों की आय बढाने के लिए उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसले लेने से किसानों की आय 10 गुना बढ सकती है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण, मोटिवेशन और आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने उद्यानिकी फसलों के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर भी ध्यान देने की बात कही है।

खाद बीज एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए*

खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है समीक्षा बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के सचिव श्री निशांत बरबडे ने बताया कि प्रदेश एवं संभाग में खाद एवं प्रमाणिक बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उन्होंने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को खाद के भंडारण एवं ई-टोकन से उर्वरक वितरण पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि संभाग में 58 प्रतिशत बोवनी हो चुकी है। इस बार कम वर्षा होने के कारण गेहूं के स्थान पर सरसों, मसूर व अलसी जैसी कम पानी वाली फसलों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने संचार माध्यमों से छोटे-छोटे वीडियों के जरिये किसानों को जागरूक करने के साथ ही कम पानी वाली फसलों के बीज कहां उपलब्ध होंगे यह भी बताने के लिए कहा है।

,बैठक में बताया गया कि सरकार द्वारा प्रमाणिक बीज की जानकारी किसान तक पहुंचाना आवश्यक है। निर्देश दिए गए कि लघु सीमांत किसानों को प्रमाणिक बीज मिले यह सुनिश्चित किया जाए। प्रमाणिक बीज कहा मिलेंगे इसका प्रचार-प्रसार करना आवश्यक है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देश दिए है कि उर्वरक बीज एवं कीटनाशक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्यवाही की जाना आवश्यक है। उन्होंने मंदसौर, नीमच एवं आगर जिले के कलेक्टरों को नकली उर्वरक पर विशेष नजर रखने तथा इसकी रोकथाम करने के लिए कहा है।

बैठक में किसानों को फसल बीमा के प्रति आकर्षित करने के लिए कहा गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2026-27 में संभाग में 23 लाख 64 हजार 307 ऋणी तथा 18210 अऋणी कृषकों का फसल बीमा किया गया है। किसानों को प्रेशराईज्ड पाईप प्रणाली से सिंचाई करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए है। कृषि उपज मंडी के प्रबंधन में टेक्नोलोजी का प्रयोग करते हुए मंडी प्रांगण का अधिक से अधिक उपयोग करने तथा जिले की किसी एक मंडी को हाईटेक मंडी में परिवर्तित करने के लिए कहा गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि मंडियां अपना व्यवसाय बढ़ाए। मंडी के माध्यम से किसानों को कितनी सेवाएं दी जा सकती है इस पर विचार किया जाए तथा मंडी में आने वाले किसानों का अनुभव कैसे सुगम हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

नरवाई जलाने पर रोक लगाई जाए

कृषि उत्पादन आयुक्त ने नरवाई जलाने पर रोक लगाने के लिए अभी से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि गेहूं की



कटाई के समय पंजाब एवं अन्य राज्यों से आने वाले हार्वेस्टरों तथा स्थानीय हार्वेस्टरों पर कटर लगे हुए हो यह सुनिश्चित किया जाए। जिन हार्वेस्टरों पर कटर नहीं हो उन पर जप्ती की कार्यवाही की जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा है कि किसानों को नरवाई जलाने के बजाय इसको अन्य उपयोग में लेकर आय का साधन बनाने की समझाइश दी जाना आवश्यक है।

उद्यानिकी फसलो के लिए क्लस्टर बनेंगे*

बैठक में उद्यानिकी फसलों से होने वाली आय के बारे में चर्चा की गई तथा इसके लिए शासन द्वारा संचालित विभन्न योजनाओं का लाभ किसानों को किस तरह मिले इस पर भी विचार किया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि जहां जहां उद्यानिकी फसलों के क्लस्टर बनाए जाए उन स्थानों पर प्रोसेसिंग यूनिट एवं कोल्ड चेन बनाना आवश्यक है। उद्यानिकी फसले यद्यपि अधिक लाभ देती है परंतु इनके साथ रिस्क भी जुडी होती है इसलिए क्लस्टर में ही इनका उत्पादन किया जाए जिससे बीमा कवर मिल सके। उज्जैन जिले में कटफ्लावर एवं फ्लावर क्लस्टर के लिए कायथा, झारडा, इंगोरिया, कासमपुर, कालियादेह सहित 65 ग्राम चयनित किए गए है। यह क्लस्टर 3000 एकड में विकसित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने इसके लिए कॉमन मार्केटिंग एवं कोल्ड चेन का व्यवस्थित विकास करने के निर्देश दिए है।

बैठक के प्रथम सत्र में आयुक्त पंजीयक एवं सहकारी संस्थाएं श्री दीपक सिंह, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ श्री अभिजीत अग्रवाल, आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री सौरभ कुमार सुमन, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री उमाशंकर भार्गव, संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, अपर आयुक्त उज्जैन संभाग सुश्री ऋचु बाफना, उज्जैन कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह एवं संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे।

नस्ल सुधार और कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जाए

बैठक के द्वितीय सत्र में प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग श्री सुदाम खाड़े के द्वारा विभाग के अंतर्गत नस्ल सुधार, उन्नत पशु नस्ल और कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिए जाने, संगठित तरीके से चारे का उत्पादन किए जाने और पशुओं के टीकाकरण और पशुस्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गए। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत उज्जैन संभाग की प्रगति की समीक्षा की गई। आगर-मालवा, शाजापुर और उज्जैन में निर्धारित लक्ष्यानुसार बैंक द्वारा प्रकरणों के संवितरण को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव श्री खाड़े ने कहा कि यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, इसमें प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाए। आचार्य विद्यासागर योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि संभाग में निर्धारित लक्ष्य 162 के विरुद्ध 114 प्रकरण वितरित किए जा चुके हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि राज्य में उन्नत पशुओं के उत्प्रेरण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं लघु तथा सीमांत पशुपालकों को उच्च उत्पादन क्षमता वाले पशु प्राप्त हों, इस उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए राज्य शासन के अनुदान पर उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली दो दुधारू भैंसें, जिनका औसत दुग्ध उत्पादन आठ से 10 लीटर हो, प्रदाय की जाएंगी।

योजना की इकाई लागत 2.95 लाख रुपए है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान तथा अजा एवं अजजा के लिए 75 प्रतिशत अनुदान प्रदाय किया जाता है। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 10 से 15 के समूह में स्थानीय पशु चिकित्सक के साथ पशु चयन के लिए हरियाणा राज्य के पशु चयन स्थल तक ले जाया जाता है, जहां हितग्राही द्वारा पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में सभी मापदंडों के अनुसार पशुओं का चयन कर जिला अथवा विकासखंड स्तर तक परिवहन कर लाए जाते हैं। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि इस योजना का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पशुपालक इसके बारे में जागरूक हो सकें।

बैठक में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत ग्राम को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ सहकारिता के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय का प्रसार करना है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। प्रत्येक जिले के एक ऐसे ग्राम का चयन किया जाएगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या न्यूनतम 2000 हो और जिसमें गोवंश की न्यूनतम संख्या 500 हो। ग्रामों का चयन कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श से किया जाएगा।

इसी प्रकार गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसमें समस्त विधानसभा क्षेत्रों में चयनित 208 वृंदावन ग्रामों में श्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक गायों के पालकों की प्रतियोगिता होगी। इसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपए और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। हर वर्ष प्रत्येक वृंदावन ग्राम में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। इस वर्ष 2026-27 में प्रतियोगिता का आयोजन गोवर्धन पूजा पर किया जाएगा।

बैठक में साइलेज, हरा चारा यूनिट के बारे में भी विस्तार से बताया गया। जानकारी दी गई कि हरे चारे की पूर्ति साइलेज के द्वारा की जा सकती है। हरे चारे को 65 से 70 प्रतिशत नमी पर काटकर, बारीक कुट्टी कर, हवा रहित अवस्था में दबाकर भंडारण किया जाता है। इससे पशुओं को वर्ष भर एक जैसा पौष्टिक आहार उपलब्ध होता है और दुग्ध उत्पादन, गर्भधारण दर और प्रजनन क्षमता में भी सुधार आता है। प्रमुख सचिव श्री खाडे ने संभाग के सभी जिलों में क्रियाशील इकाइयों की स्थापना निर्धारित लक्ष्यानुसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कस्टमर हायरिंग सेंटर्स के साथ समन्वय कर कार्य किया जाए।

'खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा उन्हेल एवं नागदा में मावा विक्रेताओं पर कार्यवाही'



उज्जैन कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा अमानक/मिलावटी खाद्य सामग्री निर्माण/विक्रय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा त्यौहार को ध्यान में रखते हुए मावा, घी, मिठाई, तेल आदि खाद्य पदार्थों पर विशेष निगरानी की जा रही है। विभाग की टीम द्वारा मावा व घी निर्माण स्थलों व विक्रेताओं की जांच की जा रही है। टीम द्वारा मावा एवं घी आदि में नमूना कार्यवाही के पूर्व खाद्य पदार्थों में स्टार्च, शर्करा, वनस्पति आदि की मिलावट पहचाने के लिये प्रारम्भिक परीक्षण किया जा रहा है। प्रारम्भिक परीक्षण में यदि मावा, घी आदि में किसी प्रकार की मिलावट की आशंका होने पर मावा, घी आदि के स्टॉक को जप्त कर विक्रय रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा आज उन्हेल एवं नागदा में मावा निर्माताओं व विक्रेताओं की जांच की गई, जहाँ पर प्राथमिक परीक्षण व्हह्लह्वस्रश्वह्लद्धठ्ठ टेस्ट आदि नेगेटिव पाये गये।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय शिविर तहसील नागदा में आयोजित किया जाएगा

उज्जैन । मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत शुक्रवार 30 अक्टूबर को जिला स्तरीय शिविर का आयोजन तहसील नागदा में किया जाएगा। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार अभियान के अंतर्गत तहसील नागदा में भ्रमण, निरीक्षण एवं जनसंवाद के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश दिए है कि समस्त विभागों के जिला प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ उपरोक्त स्थान के सभी वार्डों का भ्रमण कर शिकायतों एवं आवेदन-पत्रों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करेंगे। प्रगति की समीक्षा कलेक्टर द्वारा चिन्हित स्थान पर की जाएगी। अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण, लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरण, भूमि संबंधी (नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा) लंबित प्रकरण, न्यायालयीन आदेशों के बावजूद राजस्व अभिलेखों में अमल न होने वाले प्रकरण, सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी निर्माण, आयुष्मान कार्ड निर्माण, समग्र आईडी की ई-केवाईसी एवं आधार कार्ड निर्माण/अपडेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास उपलब्धता, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल एवं टंकी निर्माण की स्थिति, आंगनवाड़ी निरीक्षण एवं बच्चों के वजन-ऊँचाई मापन, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ एवं उपकरणों की उपलब्धता, स्कूल-कॉलेज में उपस्थिति एवं शिक्षा की गुणवत्ता, खाद-बीज एवं अन्य आदानों की उपलब्धता, राशन दुकानों का निरीक्षण एवं जन फीडबैक, सड़क-तालाब-अमृत सरोवर-कुआँ आदि शासकीय परिसंपत्तियों का निरीक्षण, आईटीआई, तहसील, कृषि उपज मंडी, पुलिस थाना, लोक सेवा केंद्र, छात्रावास आदि शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण, खाद-बीज दुकान, गैस गोदाम, पेट्रोल पंप आदि निजी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, सार्वजनिक व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की समीक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि प्रकरणों पर सुनवाई कर त्वरित निराकरण किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 07 अगस्त 2026 से जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित समाधान, शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लोक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

नि:शुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में 52 रोगी हुए लाभान्वित शरद ऋतु में होता है पित्त का प्रकोप, विरेचन चिकित्सा है श्रेष्ठ



उज्जैन । शासकीय आयुर्वेद औषधालय करोहन के द्वारा ग्राम कोकिलाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. मनीषा पाठक ने बताया कि चिकित्सा शिविर के माध्यम से 52 रोगी लाभान्वित हुए तथा निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया। शिविर में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र जैन ने ग्रामवासियों को शरद ऋतुचर्या के बारे में बताया कि शरद ऋतु (अश्विन और कार्तिक मास) के आगमन के साथ प्रारंभ होती है। यह अपने साथ पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाती है।

शरद ऋतु में शरीर में पित्त दोष का प्रकोप बढ़ता है। अतः मधुर, शीतल, पचने में आसान एवं ठंडी प्रकृति के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पुराना चावल, गेहूँ, मूंग दाल, परवल, लौकी, करेला जैसी हल्की और कड़वी सब्जी खाना चाहिए। आँवला, अनार और नारियल पानी का सेवन तथा तिक्त रस युक्त नीम, गिलोय, त्रिफला से सिद्ध घी का सेवन पित्त के शमन के लिए श्रेष्ठ होता है। अत्यधिक तीखा, खट्टा, मसालेदार भोजन, दही और शराब का सेवन अहितकर होता है।

सामुदायिक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इरफान खान ने बताया कि शरद ऋतु में ओस, क्षार, भरपेट भोजन, तेल, वसा, तीक्ष्ण धूप, दिन में सोना और पूर्वी हवा अत्यधिक अहितकर होती है। आयुर्वेद के अनुसार प्रकुपित पित्त दोष के निर्हरण करने में विरेचन श्रेष्ठ होता है। शिविर में योग सत्र का संचालन श्रीमती रेखा मालवीय ने किया। इस अवसर पर प्रधान अध्यापक संजय शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्मला तिवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीताचरण, सहायिका पूनम राठौर सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।

सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने में भेदभाव का आरोप, भाजपा समर्थक संतों को बचा रहा प्रशासन

उज्जैन। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर अखिल भारतीय मठ मंदिर सनातन धर्म मोर्चा ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। मोर्चा का कहना है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने में दोहरी नीति अपना रहा है। एक तरफ किसानों और कुछ चुनिंदा आश्रमों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं रसूखदार और सत्ता समर्थक लोगों के व्यावसायिक निर्माणों को बख्शा जा रहा है।

मोर्चा अध्यक्ष किशोर सिंह कुशवाह ने कहा कि सिंहस्थ भूमि केवल मेले के लिए आरक्षित है। इसके बावजूद शिप्रा नदी से लेकर बड़नगर रोड और मंगलनाथ क्षेत्र तक सरकारी भूमि पर मठ और आश्रम की आड़ में बड़े पैमाने पर लॉज, गेस्ट हाउस और गार्डन बनाकर व्यवसाय किया जा रहा है।

हाल ही में प्रशासन ने कुछ आश्रमों और लॉज को हटाया है जो स्वागत योग्य है, लेकिन चिंतामण रोड स्थित शनि मंदिर के आसपास और पीछे की सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए पक्के गेस्ट हाउसों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कुशवाह ने बताया कि जिस भूमि पर शनि मंदिर बना है, वह भी सरकारी है। तत्कालीन कलेक्टर अजातशत्रु ने यहां से प्रतिमा हटाने के आदेश भी दिए थे।

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कुशवाह ने पूछा कि जिन संतों के मठ तोड़े गए हैं, क्या वे कांग्रेस विचारधारा के थे और जिनके अतिक्रमण नहीं हटाए गए, क्या वे भाजपा का समर्थन करते हैं। प्रशासन को इस भेदभाव का जवाब देना चाहिए कि जब किसानों के अतिक्रमण हटाए जाते हैं तो साधु-संतों के नाम पर हुए व्यावसायिक अतिक्रमणों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही।

ड्रोन सर्वे और व्यावसायिक उपयोग पर लगे रोक- मोर्चा ने प्रशासन के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखते हुए कहा है कि सिंहस्थ क्षेत्र का ड्रोन और राजस्व रिकॉर्ड के माध्यम से संपूर्ण सर्वे कराया जाए।

तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 का शुभारंभ, युवाओं को तंबाकू से दूर रहने की दिलाई शपथ तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी आवश्यक-डॉ. विक्रम रघुवंशी



उज्जैन । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम रघुवंशी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में बुधवार को जिला चिकित्सालय उज्जैन में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉ. संगीता पलसानिया ने की। अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आम नागरिकों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को तंबाकू का सेवन नहीं करने तथा अन्य लोगों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई।

जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के नोडल अधिकारी डॉ. शिव मेन्या ने बताया कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे मुंह एवं फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग सहित अनेक गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू का दुष्प्रभाव केवल सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी पड़ता है।

युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना तथा इसके सेवन के आदी लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम रघुवंशी ने युवाओं एवं आम नागरिकों से तंबाकू सेवन से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं तंबाकू का सेवन नहीं करने के साथ ही अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना चाहिए। कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जितेंद्र सिंह राजपूत, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. निधि जैन, अस्पताल प्रबंधक श्रीमती हिमांगी चौहान, सहायक अस्पताल प्रबंधक श्रीमती वर्षा चौहान सहित जिला चिकित्सालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सफलता की कहानी कुपोषण के पूर्ण प्रबंधन से मयंक हुआ कुपोषण से मुक्त, अब सेहत में सुधार



उज्जैन । जिले के खाचरौद के आक्यानजीर क्षेत्र के ग्राम मोकड़ी निवासी श्री शालिदास बागवान व श्रीमती पूजा का बेटा मयंक जब 4 माह का था, जन्म से ही अत्यंत कमजोर था, जिस कारण मयंक के माता-पिता परेशान रहते थे। मयंक के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होने के कारण उसके माता-पिता उसे लेकर मिडिल अस्पताल सामरीद, जिला उज्जैन आए, जहां पर चिकित्सक द्वारा मयंक का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं बताया कि मयंक अत्यंत कमजोर है। इसका वजन मात्र 4 किलो 305 ग्राम है, जो इसकी उम्र की तुलना में सामान्य नहीं है।

इसे खून की भी बहुत कमी है। यह गंभीर एनीमिया से ग्रसित है, अर्थात यह कुपोषण के लक्षण हैं। इसी कारण से इसकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए यह अक्सर बीमार रहता है। यदि मयंक के कुपोषण का पूरा उपचार एवं पूर्ण प्रबंधन भर्ती रखकर किया जाता है, तो मयंक को कुपोषण से मुक्त किया जा सकता है। चिकित्सकों की बातों से प्रेरित होकर मयंक के माता-पिता मयंक को अस्पताल में भर्ती करने हेतु सहमत हो गए।

चिकित्सक द्वारा मयंक को सिविल अस्पताल खाचरौद में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया गया, जहां पर मयंक की आवश्यक जांच करवाई एवं उपचार प्रारंभ किया। पोषण पुनर्वास केंद्र में मयंक को दो सप्ताह भर्ती रख आवश्यक उपचार एवं कुपोषण का पूर्ण प्रबंधन किया। चिकित्सक डॉ. संदीप दुगरवाल व पोषण प्रशिक्षक ज्योति वर्मा एवं पोषण पुनर्वास केंद्र में कार्यरत स्टाफ द्वारा पूर्ण निगरानी की एवं उचित देखभाल की, जिसके फलस्वरूप मयंक कुपोषण से मुक्त हो गया। 14 दिन तक उचित उपचार एवं कुपोषण के पूर्ण प्रबंधन के फलस्वरूप मयंक का वजन बढ़कर 4 किलो 995 ग्राम हो गया। स्वस्थ होने के पश्चात मयंक को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब मयंक छह माह से अधिक का हो गया है। पोषण पुनर्वास केंद्र से डिस्चार्ज होने के बाद मयंक की माता को मयंक को स्तनपान कराने की सलाह दी गई एवं निरंतर पोषण आहार बनाकर खिलाने का प्रशिक्षण दिया गया। डिस्चार्ज के बाद घर पर पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है।

घर पर ही पोषण आहार मिलने से उसका वजन और भी बढ़ेगा। डिस्चार्ज के बाद मयंक का नियमित रूप से फॉलोअप भी लिया जा रहा है। तीसरी बार जब मयंक का फॉलोअप लिया गया, तो उसका वजन 5 किलो 820 ग्राम हो चुका था। अब मयंक सामान्य बच्चों की तरह जीवन जी रहा है। मयंक के माता-पिता भी अब खुश हैं कि उनका बेटा कुपोषण से मुक्त हो सका। पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती के दौरान मयंक को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं एवं पूर्ण उपचार उपलब्ध करवाया गया। डिस्चार्ज के समय मयंक के माता-पिता को प्रोत्साहन राशि 2520/- रुपये भी प्रदान की गई।

अब उज्जैन में भी जरूरतमंदों की मदद कर सकेंगे सोनू सूद



उज्जैन। फिल्म अभिनेता एवं समाजसेवी सोनू सूद की संस्था सोनू सूद चैरिटी क्लब की एन्ट्री मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में हुई है।

विगत दिनों इंदौर रोड़ स्थित निजी होटल प्लेटेल में आयोजित कार्यक्रम में शहर के समाजसेवियों व गणमान्यजनों की उपस्थिति में सोनू सूद चेरिटी क्लब का गठन किया गया। इसके पूर्व यह क्लब मध्यप्रदेश के देवास, इंदौर सहित अन्य कई शहरों में अपनी सेवा गतिविधियों का आगाज कर चुका है।

नवनियुक्त क्लब सदस्य महेश चैहान के अनुसार क्लब का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, समाजसेवा की गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं अधिक से अधिक लोगों को सेवा कार्यों से जोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना रहेगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्जैन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय थे।

युवा उत्सव की गतिविधि अत्यंत सराहनीय: ज्योति दुबे कलाकारों को मंच देना शासन की अच्छी पहल: चैतन्य मिश्रा

जिला स्तरीय युवा उत्सव में लोकनृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला और कविता लेखन की प्रस्तुतियों ने बांधा समां

अनूपपुर। (अविरल गौतम) मध्य प्रदेश शासन के युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर रत्नाकर झा, पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी जगनाथ मरकाम के मार्गदर्शन में 28 अक्टूबर 2026 को जिला खेल परिसर, माइकल क्लब में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रक्षित निरीक्षक श्रीमती ज्योति दुबे तथा विशिष्ट अतिथि जिला वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के शहडोल संभागीय अध्यक्ष चैतन्य मिश्रा रहे।

ज्योति दुबे ने की आयोजन की सराहना

मुख्य अतिथि रक्षित निरीक्षक ज्योति दुबे ने युवा उत्सव की सराहना करते हुए कहा कि यह अत्यंत अच्छा और प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि पहले उनकी धारणा थी कि खेल



विभाग में केवल खेल गतिविधियां ही होती हैं, लेकिन यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई।

उन्होंने आयोजन से जुड़े विभागीय कर्मचारियों और अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी।

चैतन्य मिश्रा बोले कलाकारों को मंच देना शासन की अच्छी पहल

विशिष्ट अतिथि चैतन्य मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन की यह एक अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है।

ऐसे आयोजनों से युवाओं की प्रतिभा को पहचान मिलती है और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है।

विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभा

युवा उत्सव के अंतर्गत समूह लोकनृत्य, समूह लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला और कविता लेखन सहित विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से कला एवं रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं निर्णायकों को भी ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया।

आयोजन में इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका

कार्यक्रम का मंच संचालन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विकासखंड समन्वयक दिनेश कुमार सिंह चंदेल ने किया।

आयोजन के माध्यम से युवाओं को खेल के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों में आगे बढ़ने का अवसर मिला।

जिले में नवाचार: धनतेरस-दीपावली पर महिलाओं की सुरक्षा में उतरेगी कोतवाली की 'महिला ब्रिगेड', बाजार में करेगी गश्त



शहडोल। (अविरल गौतम) धनतेरस और दीपावली पर बाजार में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए शहडोल कोतवाली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई पहल शुरू की है। थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने 'महिला ब्रिगेड' नाम से विशेष पुलिस दल का गठन किया है। यह टीम बाजार के उन इलाकों में पैदल गश्त करेगी, जहां खरीदारी के लिए महिलाओं की अधिक भीड़ उमड़ती है। बुधवार से इस पहल की शुरुआत हो गई है।

गहने पहनकर बाजार आने वाली महिलाओं पर नजर रखती हैं महिला चोर

त्योहारों के दौरान महिलाएं खरीदारी के लिए सज-धजकर घरों से निकलती हैं। कई महिलाएं सोने के मंगलसूत्र, चेन और अन्य आभूषण पहनकर बाजार पहुंचती हैं। ऐसे में भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने वाली महिलाओं के सक्रिय होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोतवाली पुलिस ने महिला ब्रिगेड को मैदान में उतारा है। टीम बाजार में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी।

भीड़ रहने तक रहेगी टीम

महिला ब्रिगेड में चार महिला पुलिसकर्मियों के साथ एक पुलिस अधिकारी या विवेचक की तैनाती की गई है। यह दल ज्वेलरी, कपड़े और बर्तन की दुकानों सहित बाजार के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल भ्रमण करेगा। पुलिस ने टीम की ड्यूटी दो पालियों में निर्धारित की है। पहली टीम सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक तैनात रहेगी, जबकि दूसरी टीम शाम चार बजे से रात नौ बजे या बाजार में भीड़ रहने तक गश्त करेगी।

बढ़ाई जाएगी टीमों की संख्या

थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि आगामी त्योहारों के दौरान बाजार में महिलाओं की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से महिला ब्रिगेड बनाई गई है। बुधवार को कोतवाली से दल को रवाना कर इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर दो और दल गठित किए जाएंगे। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार आने वाली महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है।



मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर के निर्देशानुसार भोपाल संभाग अध्यक्ष श्री विकास चौहान के नेतृत्व में भोपाल के समस्त कर्मचारियों को दीपावली पूर्व ष्ठ एरियर राशि भुगतान होने पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्रीमती विजेता सूर्यवंशी मैडम का आभार व्यक्त किया गया इस अवसर पर जिला सचिव बालेन्द्र सिंह , जिला कोषाध्यक्ष जितेन्द्र चौहान , कोलार तहशील अध्यक्ष अशोक जाट , कोलार सचिव मनीष यादव फंदा, कोषाध्यक्ष चंद्रेश सिंह चौहान , उमेश चौधरी , हीरानंद नरवरिया आदि उपस्थित रहे । ज्ञातब्य है कि भोपाल महानगर अध्यक्ष अवनीश श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले ही क्ष्श्वह्र मैडम को ज्ञापन देकर अवगत कराया था कि दीपावली पूर्व सभी के रुके हुए एरियर्स का भुगतान कराया जाए ताकि सभी कर्मचारी त्योहार का वास्तविक आनंद अपने परिवार के साथ ले सकें । ज्ञापन में अर्जित अवकाश की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की माँग के साथ अन्य विषय भी BEO मैडम के संज्ञान में लाये गये हैं जिनपर शीघ्र ही कार्यवाही करने का आस्वाशन दिया गया है ।

जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत धनवार रोड घोड़छत्र पुल के पास अंधे मोड़ पर ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत अनयंतरित ट्रैक्टर पलटा, मौके पर चालक की दर्दनाक मौत

उमरिया। (दीपक द्विवेदी) जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धनवार- ग्राम हड़हा के बीच अनियन्त्रित ट्रैक्टर पलट गया है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खबर है कि इस हादसे में चालक सतीश साहू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। नौरोजाबाद पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर नोरोजाबाद पुलिस पहुंची है,ज़रूरी तफ्तीश पंचनामा बना कर शव को कब्जे में लीया गया है।सूत्रों की माने तो मृतक ट्रैक्टर लेकर वापस ग्रह ग्राम बरही जा रहा था,इसी दौरान हादसा घटित हो गया बताया जा रहा है कि ट्रेक्टर स्पीट में था और अंधा मोड़ होने के करण चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर पलटा गया।फिलहाल घटना किन कारणों से हुई है यह साफ़ नही हो पा रहा है,खबर है कि घटना स्थल दोनों गांवों के बीच घोडछत्र नदी पर बनी पुलिया के करीब हादसा हुआ है।उक्त दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर बरही निवासी मालिक का बताया जा रहा है। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत धनवार रोड घोड़छत्र पुल के पास अंधे मोड़ पर ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक



मौत। अनयंतरित ट्रैक्टर पलटा, मौके पर चालक की दर्दनाक मौत उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धनवार- ग्राम हड़हा के बीच अनियन्त्रित ट्रैक्टर पलट गया

379fd655-0188-4d41-af37-dfeb66fc99dd

है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खबर है कि इस हादसे में चालक सतीश साहू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। नौरोजाबाद पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर नोरोजाबाद पुलिस पहुंची है,ज़रूरी तफ्तीश पंचनामा बना कर शव को

489fxcee-909e-4178-8e10-baff51cea6e4

कब्जे में लीया गया है।सूत्रों की माने तो मृतक ट्रैक्टर लेकर वापस ग्रह ग्राम बरही जा रहा था,इसी दौरान हादसा घटित हो गया बताया जा रहा है कि ट्रेक्टर स्पीट में था और अंधा मोड़ होने के करण चालक नियंत्रण खो बैठा और

5648dac4-1e63-4926-85ष7-f6885a30d78e

ट्रैक्टर पलटा गया।फिलहाल घटना किन कारणों से हुई है यह साफ़ नही हो पा रहा है,खबर है कि घटना स्थल दोनों गांवों के बीच घोडछत्र नदी पर बनी पुलिया के करीब हादसा हुआ है।उक्त दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर बरही निवासी मालिक का बताया जा रहा है।

उमरिया जिले के जनपद पंचायत मानपुर के हलफल-भादर नदी पर पुल और सड़क की मांग को लेकर तीसरे दिन भी धरना

प्रशासन का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, कांग्रेस ने ग्रामीणों के आंदोलन को दिया समर्थन

उमरिया। (दीपक द्विवेदी) जिले के जनपद पंचायत मानपुर की ग्राम पंचायत उमरिया-बकेली में मानव समाज सेवा समिति उमरिया-बकेली एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हलफल-भादर नदी पर पुल निर्माण तथा उमरिया-बकेली तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन सामूहिक धरना गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन के तीसरे दिन भी प्रशासन की ओर से कोई प्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने नहीं पहुंचा। हालांकि मौके पर पुलिस व्यवस्था मौजूद रही। धरना स्थल पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंजी. विजय कोल के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और आंदोलनरत ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी मांगों को समर्थन दिया। विजय कोल ने कहा कि हलफल नदी पर पुल और उमरिया-बकेली तक सड़क निर्माण की मांग पूरी तरह जायज और जनहित से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन से चर्चा करेगा तथा समस्या के समाधान के लिए शासन-प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से मांग रखी जाएगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आंदोलनकारियों से अपील की कि आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी तरीके से जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास से सीधे जुड़ी हुई है तथा कांग्रेस जनहित के इस मुद्दे पर ग्रामीणों के साथ खड़ी है। धरना स्थल पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीमती अंजू सिंह इंदवार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गौरीशंकर मिश्रा, उमरिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मिथलेश राय, पूर्व प्रत्याशी तिलक राज सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी अमर बहादुर सिंह, बेटी बाई रजक, अयोध्या प्रजापति, रवि सेन, भोला पटेल एवं प्रकाश द्विवेदी सहित कांग्रेसजन मौजूद रहे।



पुल के अभाव में बढ़ रही परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि हलफल-भादर नदी पर पुल नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क एवं पुल निर्माण से उमरिया-बकेली सहित आसपास के गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। मानव समाज सेवा समिति उमरिया-बकेली एवं स्थानीय ग्रामीणों ने मांगें पूरी होने तक अनिश्चितकालीन सामूहिक धरना जारी रखने का निर्णय लिया है।

जिले के गोहपारू में बाघ का खौफनाक हमला: गोहपारू में मवेशी चराने गए युवक का शव मिला, वन विभाग पर गुस्सा फूटा

शहडोल। (अविरल गौतम) जिले के जनपद पंचायत गोहपारु में मवेशी चराने जंगल गए चरवाहे की बाघ के हमले में मौत हो गई। लापता होने के बाद दूसरे दिन उसका शव जंगल में मिला।

घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर बाघ की मौजूदगी की जानकारी होने के बावजूद पर्याप्त चेतावनी और गश्त नहीं करने का आरोप लगाया हैजिले में जंगली हाथियों के आतंक के बीच अब बाघ की दहशत ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गोहपारू क्षेत्र के जंगल में मवेशी चराने गए एक चरवाहे पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से लापता चरवाहे का शव दूसरे दिन जंगल में मिला। शव के कुछ हिस्से को बाघ द्वारा खाए जाने की बात भी सामने आई है। घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल हैजानकारी के अनुसार गोहपारू थाना क्षेत्र का सोनशाह यादव अपने साथी के साथ गांव के पास स्थित पठारी जंगल में मवेशी चराने गया था। इसी दौरान उसका साथी मवेशियों के साथ पहले ही रुक गया।



कुछ देर बाद जंगल से बाघ की दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद साथी डरकर गांव पहुंचा और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सोनशाह के परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश के लिए जंगल की ओर निकले। वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। रात में तलाश की गई, लेकिन बाघ की दहशत और अंधेरे के कारण सफलता नहीं मिली। अगले दिन सुबह जंगल में सोनशाह का शव मिला।जानकारी के बावजूद नहीं हुई मुनादी

घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि जिस क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी थी, इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को पहले से थी। इसके बावजूद गांव में सही तरीके से मुनादी नहीं कराई गई और न ही प्रभावी गश्त की गई।

ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी कोयला और रेत पकड़ने में व्यस्त हैं। यदि समय रहते लोगों को सतर्क किया जाता तो शायद सोनशाह की जान बच सकती थीगोहपारू रेंजर हेमंत प्रजापति का कहना है कि बाघ की मौजूदगी की जानकारी वन विभाग को थी और मृतक को कर्मचारियों ने जंगल की ओर जाने से रोका था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

वन विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर बाघ के पगमार्क मिले हैं। विभाग ने ग्रामीणों से बाघ के विचरण क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की है। मृतक की पत्नी को 10 हजार रुपये की तत्काल सहायता दी गई है, जबकि शेष राशि देने की प्रक्रिया जारी है।

जिले के नौरोजाबाद शासकीय स्कूल में हुई चोरी का खुलासा: नौरोजाबाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी गया मशरूका बरामद

उमरिया। (अविरल गौतम) जिले के नौरोजाबाद आरोपियों द्वारा शासकीय हाई स्कूल नया गाँव, ग्राम कल्दा में चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम। ज़्पुलिस अधीक्षक उमरिया श्री विजय भागवानी, अति. पुलिस अधीक्षक उमरिया श्री आलोक शर्मा के निर्देशन एवं एसडीओपी पाली श्री ललित गठरे के मार्गदर्शन में पुलिस टीम को मिली सफलता घटना का विवरण - फरियादी झाम सिंह परस्ते प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल नया गाँव ग्राम कल्दा ने थाना नौरोजाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात आरोपियों द्वारा विद्यालय के ताले तोड़कर शैक्षणिक एवं अन्य उपयोगी सामग्री चोरी कर ली है । रिपोर्ट पर थाना नौरोजाबाद में अपराध क्रमांक 431/2026, धारा 305(5), 331(4) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। चोरी गई सामग्री में सीसीटीवी कैमरा, एम्पलीफायर, माइक, सोलर बैटरियाँ, कलर प्रिंटर, गैस सिलेंडर, कैसियो म्यूजिक सिस्टम, साउंड बॉक्स, मिक्सर, सीपीयू, गैस चूल्हा, बोर्ड एवं इन्वर्टर सहित कुल लगभग 1,25,000/- मूल्य । पुलिस कार्यवाही का विवरण - फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नौरोजाबाद में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। विवेचना के दौरान चोरी गई सामग्री एवं आरोपियों की तलाश हेतु लोगो से पूछताछ एवं अन्य तरीकों से साक्ष्य संकलित किये गये । संकलित किये गये भौतिक एवं तकनीकी



साक्ष्यो के आधार पर कुछ संदेहियों को नाम सामने आये । मामले में संदेहियों से बारीकी से पूछताछ की गई जिस पर संदेही विपिन पाल निवासी ग्राम देवरी मजरा, शिवम नामदेव निवासी ग्राम देवरी मजरा, सागर सिंह निवासी ग्राम देवरी, ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम जरहा घूरमारा टोला द्वारा मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया । प्रकरण में आरोपियों के कब्जे से चोरी गया मसरूका बरामद किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

जिले के बिरसिंहपुर पाली में बजरंग पावर की दादागिरी! आदिवासियों की जमीन पर पेड़ कटाई का आरोप, शिकायतों के बाद भी सवाल बरकरार

उमरिया। (दीपक द्विवेदी) जिले के बिरसिंहपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम गिठौरी में बजरंग पावर कंपनी और आदिवासी ग्रामीणों के बीच जमीन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने कंपनी पर उनकी पुश्तैनी भूमि पर लगे पेड़ों की कथित तौर पर बिना सहमति कटाई करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब वे पेड़ काटने का विरोध करते हैं और अनुमति संबंधी जानकारी मांगते हैं, तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ग्रामीणों की शिकायतों और जमीन संबंधी विवाद के बीच पेड़ कटाई की कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है।

पुश्तैनी जमीन पर अधिकार की लड़ाई

ग्राम गिठौरी के आदिवासी समुदाय के ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरजी खसरा नंबर 42 की भूमि उनके पूर्वजों की है। इस जमीन पर उनके परिवार लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं और यहां पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, भूमि को लेकर उन्होंने पाली न्यायालय में सिविल वाद क्रमांक 32/2025 प्रस्तुत किया है। उनका दावा है कि जमीन से संबंधित विवाद की जानकारी होने के बावजूद बजरंग पावर कंपनी के कर्मचारी उनकी सहमति के बिना पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने मौके पर पहुंचकर कटाई रोकने की बात कही और अनुमति के संबंध में जानकारी मांगी, तो उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। शिकायत में धमकाने जैसी बातों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

गरीब आदिवासी आखिर किसके दरवाजे पर लगाएं गुहार

ग्रामीणों का कहना है कि वे गरीब आदिवासी परिवारों से हैं और उक्त भूमि के अतिरिक्त उनके पास खेती के लिए दूसरी जमीन नहीं है। ऐसे में जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई उनके लिए केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि आजीविका और पुश्तैनी अधिकारों से भी जुड़ा मामला है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पेड़ों की कटाई तत्काल रोकी जाए और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने वन विभाग को भी शिकायत पत्र सौंपा है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग मौके की जांच कर ग्रामीणों की शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं।

पुलिस तक पहुंचा मामला, जांच के लिए चौकी को शिकायत

इस संबंध में पाली थाना प्रभारी गोविंद सिंह धुर्वे ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। जांच के लिए आवेदन घुनघुटी चौकी भेज दिया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार, पेड़ कटाई को लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। पुलिस की ओर से शिकायत जांच के लिए भेजे जाने की जानकारी सामने आई



है, लेकिन ग्रामीणों को राहत कब मिलेगी और कथित पेड़ कटाई पर रोक लगाने के लिए क्या कार्रवाई होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

पथौरा कोल ब्लॉक और बढ़ता विवाद

भारत सरकार द्वारा आवंटित पथौरा कोल ब्लॉक, जिसमें भूमिगत और ओपनकास्ट खनन शामिल है, का उत्खनन कार्य मेसर्स बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड को मिला है। खनन परियोजना से जुड़े विवाद के बीच गिठौरी के ग्रामीणों की शिकायत ने एक बार फिर भूमि, पेड़ों और स्थानीय लोगों के अधिकारों का सवाल खड़ा कर दिया है। इस मामले में बजरंग पावर के जीएम शशिधर द्विवेदी से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल एक जगह बैठे हैं और बाद में बात करेंगे। उनका विस्तृत पक्ष फिलहाल सामने नहीं आया है।

अब प्रशासन की जवाबदेही की बारी

सवाल साफ है कि जब ग्रामीण जमीन पर अपना पुश्तैनी अधिकार होने का दावा कर रहे हैं, न्यायालय में मामला लंबित होने की बात कह रहे हैं और वन विभाग तथा पुलिस तक शिकायत पहुंच चुकी है, तो मौके पर पेड़ कटाई की वैधता की जांच कौन करेगा। क्या संबंधित अनुमति और दस्तावेजों की जांच कर ग्रामीणों को स्थिति स्पष्ट की जाएगी। कंपनी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यदि कटाई नियमों के विरुद्ध पाई जाती है, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि कंपनी के पास वैध अनुमति है, तो उसे संबंधित दस्तावेज और प्रक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए। फिलहाल गिठौरी के आदिवासी ग्रामीण जवाब और कार्रवाई की उम्मीद में हैं। प्रशासन की अगली कार्रवाई तय करेगी कि उनकी शिकायत पर केवल कागजी जांच होगी या जमीन पर भी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।

संपादकीय

प्राइवेट हॉस्पिटलस की मुनाफ़ाखोरी पर अब आर- पार की लड़ाई?



वैश्विक स्तरपर भारत में डॉक्टर को कभी भगवान का दूसरा रूप माना जाता था। मरीज अपना जीवन अपनी उम्मीदें और अपनी जीवनभर की कमाई डॉक्टर के भरोसे सौंप देता है।लेकिन जब गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज को इलाज के साथ-साथ असहनीय अस्पताल बिल महंगी दवाओं और चिकित्सा सामग्रियों की भारी कीमतों का सामना करना पड़े,तो स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर क्या किसी मरीज की मजबूरी को अस्पताल के मुनाफे का अवसर बनाया जा सकता है?क्या जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों पर पारदर्शिता और उचित नियंत्रण सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?निजी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की कीमतों तथा फार्मा कंपनियों की कथित अनैतिक विपणन गतिविधियों से जुड़ा यही गंभीर प्रश्न अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगाकि इस मामले में डॉ.संजय कुलश्रेष्ठ की जनहित याचिका और किशनचंद जैन की याचिका महत्वपूर्ण हैं।12 अक्टूबर 2026 के न्यायालयीन रिकॉर्ड में इन दोनों मामलों को 27 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।आज 27 अक्टूबर की सुनवाई के बाद पारित आदेश 29 जनवरी 2027 की निर्धारित सुनवाई का संदर्भ इस विवाद की गंभीरता को सटीकता से स्पष्ट करता है।

साथियों बात अगर हम दो याचिकाएं, एक बड़ा सवाल इलाज मरीज के लिए या मुनाफे का कारोबार? को समझने की करें तो,इस विवाद में प्रमुख रूप से रिट याचिका (सिविल) संख्या 794/2023, किशन चंद जैन बनाम एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड एवं अन्य, तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या 717/2026, डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ बनाम भारत संघ,शामिल हैं।दोनों मामलों में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष दवाओं की कीमतों, चिकित्सकीय नैतिकता और फार्मा कंपनियों की भूमिका से संबंधित मुद्दे उठे हैं।12 अक्टूबर को इन मामलों की सुनवाई के बाद 27 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। इस मामले का केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या अस्पताल दवाओं और चिकित्सा सामग्रियों को खरीदने की वास्तविक लागत से बहुत अधिक कीमत पर बेच सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कौन-सा प्रभावी कानूनी तंत्र होना चाहिए। यह केवल निजी अस्पतालों के व्यावसायिक मॉडल का प्रश्न नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण और आर्थिक न्याय से भी जुड़ा विषय है।

साथियों बात अगर हम क्या दवाओं के साथ सिरिंज ग्लव्स और स्टेंट की कीमतों पर भी लगेगी लगाम? को समझने की करें तो,अस्पताल का अंतिम बिल केवल दवाओं से नहीं बनता। उसमें सिरिंज, दस्ताने, ग्लूकोज ड्रिप, कैथेटर स्टेंट, ड्रेसिंग सामग्री और अन्य चिकित्सा उपभोग्य वस्तुओं का खर्च भी शामिल होता है। मरीज को अक्सर इन वस्तुओं के ब्रांड, वास्तविक खरीद लागत और बाजार में उपलब्ध सस्ते विकल्पों की जानकारी नहीं होती। अस्पताल में भर्ती होने के बाद तत्काल जरूरत के कारण वह हर वस्तु की कीमत की तुलना भी नहीं कर पाता।इसी परिस्थिति में सूचना की असमानता और मरीज की कमजोर सौदेबाजी की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। अस्पताल यदि अपनी ही फार्मेसी से दवाएं खरीदने का दबाव डालता है, तो मरीज को यह जानने का अवसर मिलना चाहिए कि निर्धारित दवा का कोई समान रूप से उपयुक्त विकल्प उपलब्ध है या नहीं और उसे बाहर से खरीदने की अनुमति है या नहीं।लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि हर अस्पताल- आधारित फार्मेसी की बिक्री को अनुचित कहना सही नहीं है। अस्पतालों को दवाओं के सुरक्षित भंडारण,आपूर्ति, आपातकालीन उपलब्धता और गुणवत्ता नियंत्रण का खर्च भी उठाना पड़ता है। वास्तविक प्रश्न यह है कि इन खर्चों के नाम पर कितना मार्जिन उचित है, कीमतें कितनी पारदर्शी हैं और मरीज को अनावश्यक रूप से महंगी वस्तु खरीदने के लिए तो बाध्य नहीं किया जा रहा।

साथियों बात अगर हम फार्मा कंपनियां और डॉक्टरों के बीच कथित गठजोड़ पर भी नजर को समझने की करें तो इस मामले से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष दवा कंपनियों की विपणन गतिविधियां हैं। आरोप है कि कुछ कंपनियां डॉक्टरों को उपहार, यात्रा, आतिथ्य, सम्मेलन प्रायोजन अथवा दूसरे आर्थिक लाभ देकर अपने उत्पादों के प्रचार को बढ़ावा देती हैं। यदि ऐसे लाभ किसी दवा को लिखने के निर्णय को प्रभावित करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान मरीज को होता है,जिसे अधिक महंगी दवा खरीदनी पड़ सकती है।8 अक्टूबर 2026 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने फार्मा कंपनियों की विपणन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति गठित करने का निर्देश दिया था। इस प्रक्रिया में डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों तथा अन्य लाभों पर प्रभावी नियंत्रण और कंपनियों की जवाबदेही जैसे विषय शामिल हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अनुपालन हलफनामे पर विचार के लिए 29 जनवरी 2027 की तारीख रिपोर्ट की गई है।इसलिए दवा मूल्य नियंत्रण और अनैतिक विपणन पर कार्रवाई को दो अलग-अलग,लेकिन परस्पर जुड़े सुधारों के रूप में देखना चाहिए। केवल दवा की कीमत कम करना पर्याप्त नहीं होगा, यदि दवा लिखने की प्रक्रिया में हितों का टकराव बना रहता है। इसी तरह, डॉक्टरों के लिए नैतिक नियम बनाना भी पर्याप्त नहीं होगा, यदि मरीज को दवाओं की कीमत और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी ही न मिले।



एक ही खेत से दोहरी पैदावारः कृषि और सौर ऊर्जा का संगम



कृषि ग्रामीण भारत की रीढ़ है, जबकि सौर ऊर्जा स्वच्छ बिजली के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रही है। परंपरागत रूप से खेती और सौर ऊर्जा उत्पादन के बीच भूमि के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा रही है। सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए बड़े भू-भाग की आवश्यकता होती है, जिनका उपयोग अन्यथा फसलें उगाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब एग्रीवोल्टिक्स (ऽहह्ल1श्द्यह्लड्डह्ष्द्य) नामक एक अभिनव तकनीक कृषि और सौर ऊर्जा को एक ही भूमि पर एक साथ विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रणाली में ऊँचाई पर लगाए गए सौर पैनलों के नीचे या उनके बीच फसलें उगाई जाती हैं और साथ ही बिजली भी पैदा की जाती है।

इस अवधारणा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है-क्या भारतीय किसान कृषि उत्पादन को नुकसान पहुँचाए बिना एक ही खेत से अनाज और सौर ऊर्जा, दोनों प्राप्त कर सकते हैं?

एग्रीवोल्टिक्स वह प्रणाली है, जिसमें एक ही भूमि पर कृषि उत्पादन और सौर फोटोवोल्टिक तकनीक का एक साथ उपयोग किया जाता है। सौर पैनलों को उचित ऊँचाई और दूरी पर स्थापित किया जाता है, ताकि उनके नीचे या बीच में खेती की जा सके। इस प्रणाली के अंतर्गत सब्जियाँ, पशुओं के लिए हरा चारा, औषधीय पौधे और आंशिक छाया में उगने वाली कुछ फसलें पैदा की जा सकती हैं।

पारंपरिक सौर ऊर्जा पार्कों में कृषि गतिविधियाँ कम हो सकती हैं, लेकिन एग्रीवोल्टिक्स का उद्देश्य खेती और ऊर्जा उत्पादन को साथ-साथ जारी रखना है। भारत जैसे देश में, जहाँ कृषि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह तकनीक विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ किसानों की आय के दो स्रोत विकसित करना है। किसान कृषि उपज बेचकर और सौर बिजली से भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। स्वामित्व और समझौते की शर्तों के अनुसार बिजली को विद्युत ग्रिड में बेचा जा सकता है अथवा सिंचाई पंपों और अन्य कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

सौर पैनल आंशिक छाया भी प्रदान करते हैं। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में यह छाया कुछ फसलों को अत्यधिक गर्मी से बचाने तथा मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद कर सकती है। हालाँकि, इसका लाभ फसल की किस्म, स्थानीय जलवायु, पैनलों की ऊँचाई, उनके बीच की दूरी और पौधों तक पहुँचने वाली धूप पर निर्भर करता है। एग्रीवोल्टिक्स पानी के अधिक कुशल उपयोग में भी सहायक हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण कम होने के कारण नमी अधिक समय तक बनी रह सकती है। हालाँकि, पैनलों के कारण वर्षा का पानी कुछ स्थानों पर अधिक और कुछ स्थानों पर कम गिर सकता है। इसलिए जल निकासी और पानी के वितरण का उचित प्रबंधन आवश्यक है।

इस तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती बिजली उत्पादन और कृषि उत्पादकता के बीच संतुलन बनाए रखना है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण, विकास और अनाज बनने के लिए पर्याप्त सूर्यप्रकाश की आवश्यकता होती है। अत्यधिक छाया के कारण विशेष रूप से अधिक धूप चाहने वाली फसलों की पैदावार घट सकती है।

इसलिए सभी खेतों और फसलों के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था उपयुक्त नहीं होगी। फसलों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्तेदार सब्जियाँ, कुछ चारा फसलें और छाया सहन करने वाले पौधे उचित परिस्थितियों में अच्छी तरह विकसित हो सकते हैं। इसके विपरीत, गेहूँ, धान और अन्य अधिक धूप चाहने वाली फसलों के लिए विशेष सावधानी आवश्यक है।

पंजाब में गेहूँ और धान प्रमुख फसलें हैं। इसलिए यहाँ बड़े पैमाने पर इस तकनीक को अपनाने से पहले स्थानीय परिस्थितियों में वैज्ञानिक परीक्षण किए जाने चाहिए। शोधकर्ताओं को कई फसल मौसमों के दौरान पैदावार, अनाज की गुणवत्ता, पानी की खपत, बिजली उत्पादन और किसानों के लाभ का मूल्यांकन करना चाहिए।

ऊँचे सौर पैनल लगाने के लिए प्रारंभिक निवेश काफी अधिक हो सकता है। किसानों को पैनलों के नीचे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनें चलाने में भी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसलिए पैनलों की ऊँचाई और व्यवस्था तय करते समय कृषि उपकरणों, फसलों की ऊँचाई, जल निकासी और नियमित कृषि गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए।

सरकारी सहायता, सस्ती वित्तीय सुविधाएँ, सहकारी स्वामित्व और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ साझेदारी इस तकनीक को अधिक किसानों तक पहुँचाने में मदद कर सकती है। कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मॉडल विकसित करके प्रायोगिक परियोजनाएँ शुरू करनी चाहिए।

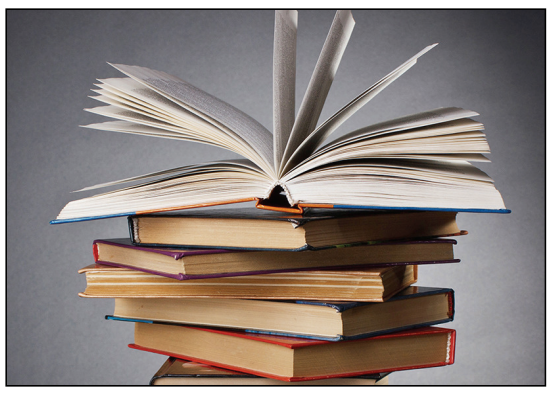
किसानों को बिजली की कीमत, रखरखाव के खर्च, भूमि के स्वामित्व और उपकरणों की मरम्मत संबंधी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट समझौते भी मिलने चाहिए। छोटे किसानों को पूँजी की कमी के कारण इस तकनीक के लाभों से वंचित नहीं रहना चाहिए।

एग्रीवोल्टिक्स भारत की कृषि परंपरा को स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों से जोड़ने का एक नया अवसर प्रदान करता है। यह किसानों की आय के स्रोत बढ़ाने, भूमि का अधिक कुशल उपयोग करने और कम कार्बन उत्सर्जन वाली बिजली पैदा करने में योगदान दे सकता है। हालाँकि, इसकी सफलता वैज्ञानिक योजना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीक अपनाने पर निर्भर करेगी।

आगे बढ़ने के लिए पहले चुनिंदा क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजनाएँ शुरू की जानी चाहिए। पारंपरिक खेती और एग्रीवोल्टिक्स के अंतर्गत होने वाली पैदावार की तुलना की जानी चाहिए तथा आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रमाणित होने पर ही इसका विस्तार किया जाना चाहिए।

खेती का भविष्य शायद भोजन और बिजली में से किसी एक को चुनने पर निर्भर न हो। उचित तकनीक, उपयुक्त फसलों और किसान-केंद्रित नीतियों के माध्यम से एक ही खेत से दोहरी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इससे ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी और भारत को स्वच्छ तथा टिकाऊ ऊर्जा के भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

किताबों का सफरः शब्दों के सहारे दुनिया की सैर



यात्रा करना जीवन के सबसे आनंददायक और ज्ञानवर्धक अनुभवों में से एक है। यह हमें नए स्थानों, संस्कृतियों, परंपराओं और लोगों से परिचित कराती है। लेकिन यात्रा करने के लिए हमेशा रेलगाड़ी का टिकट, हवाई जहाज या पासपोर्ट आवश्यक नहीं होता। कई बार केवल एक किताब ही पर्याप्त होती है। पढ़ने के माध्यम से हम दूर-दराज के देशों की सैर कर सकते हैं, प्राचीन सभ्यताओं को जान सकते हैं और अपने घर बैठे ही सदियों पुराने समय में पहुँच सकते हैं।

किताबें हमारी ऐसी अद्भुत साथी हैं, जो हमारे लिए अनगिनत संसारों के दरवाजे खोलती हैं। यात्रा से संबंधित कोई पुस्तक हमें हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों, राजस्थान के रेगिस्तानों, कश्मीर की सुंदर वादियों या लंदन की व्यस्त सड़कों तक ले जा सकती है। इतिहास की कोई पुस्तक हमें प्राचीन भारत, रोमन साम्राज्य या मिस्र की महान सभ्यता से परिचित करा सकती है। प्रत्येक पृष्ठ के साथ हमारी कल्पना नई उड़ान भरने लगती है।

किताबों के माध्यम से यात्रा करना केवल पढ़ना नहीं, बल्कि मन और मस्तिष्क का एक रोमांचक सफर है। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसके पात्रों की कल्पना करते हैं, घटनाओं को अपने मन में चित्रित करते हैं और उनसे जुड़ी भावनाओं को अनुभव करते हैं। एक अच्छा लेखक हमें ऐसा अनुभव कराता है, मानो हम अनजान गलियों में घूम रहे हों, पहाड़ों पर चढ़ रहे हों, नदियाँ पार कर रहे हों या विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों से मिल रहे हों। यह काल्पनिक यात्रा पढ़ने को मनोरंजक और शिक्षाप्रद बनाती है।

किताबें हमें दूसरी संस्कृतियों को समझने में भी सहायता करती हैं। विभिन्न देशों के बारे में पढ़कर हम उनके खान-पान, त्योहारों, भाषाओं, मान्यताओं और जीवनशैली के बारे में जान सकते हैं। यह ज्ञान विविधता के प्रति सम्मान विकसित करता है और पूर्वाग्रहों को कम करता है। हमें समझ में आता है कि भले ही लोगों की भाषाएँ और परंपराएँ अलग-अलग हों, लेकिन उनकी आशाएँ, सपने और भावनाएँ अक्सर समान होती हैं।

विद्यार्थियों के लिए किताबों के माध्यम से ज्ञान की यात्रा विशेष रूप से उपयोगी है। पाठ्यपुस्तकें आवश्यक ज्ञान प्रदान करती हैं, जबकि जीवनियाँ, यात्रा-वृत्तांत, उपन्यास और ऐतिहासिक पुस्तकें उनकी सोच का दायरा बढ़ाती हैं। वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं, आविष्कारकों और समाज सुधारकों के जीवन के बारे में पढ़ना युवाओं को रचनात्मक सोच अपनाने और जीवन में सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। किताबें शब्द-भंडार, संवाद-कौशल, एकाग्रता और तार्किक सोच को भी विकसित करती हैं।

किताबों के माध्यम से यात्रा करने का एक बड़ा लाभ यह है कि यह लगभग हर व्यक्ति की पहुँच में हो सकती है। वास्तविक यात्रा महँगी और समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन किताबें अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं और पुस्तकालयों, विद्यालयों तथा डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध हो जाती हैं। किसी छोटे गाँव में रहने वाला विद्यार्थी भी किताबों के माध्यम से दुनिया के प्रसिद्ध संग्रहालयों, दूर-दराज के प्राकृतिक पर्यावरणों और वैज्ञानिक खोजों के बारे में जान सकता है। डिजिटल पुस्तकालयों ने इस अवसर को और अधिक सुलभ बना दिया है।

हालाँकि, किताबों के सफर का वास्तविक आनंद लेने के लिए अच्छी पुस्तकों का चयन करना भी आवश्यक है। पाठकों को विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल, दर्शन और यात्रा-साहित्य जैसे विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। नियमित रूप से पढ़ना, दूसरों के साथ पुस्तकों पर चर्चा करना और पढ़ी गई बातों की डायरी बनाना इस अनुभव को अधिक सार्थक बना सकता है।

आज के डिजिटल युग में, जहाँ छोटी-छोटी वीडियो और लगातार आने वाली सूचनाएँ हमारा ध्यान आकर्षित करती रहती हैं, पढ़ने की आदत विकसित करना पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। किताबें धैर्य, गहन चिंतन और एकाग्रता को बढ़ावा देती हैं। वे हमें कुछ समय रुककर सोचने और सोशल मीडिया की खबरों से आगे बढ़कर दुनिया को समझने का अवसर प्रदान करती हैं।

अंततः, किताबें केवल छपे हुए पन्नों का संग्रह नहीं हैं। वे लोगों, संस्कृतियों, पीढ़ियों और विचारों को जोड़ने वाले पुल हैं। वे हमें उन स्थानों तक पहुँचाती हैं, जहाँ शायद हम कभी वास्तविक रूप से न जा सकें, और ऐसे लोगों से परिचित कराती हैं, जिनसे जीवन में कभी मुलाकात न हो पाए।

इसलिए, जब भी आपका कहीं घूमने का मन हो, एक अच्छी किताब उठाइए और अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। आपको एहसास होगा कि दुनिया के सबसे अद्भुत गंतव्य हमेशा नक्शों पर नहीं मिलते; उनमें से कई किताबों के पन्नों के बीच चुपचाप आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं।

राजनेता मेटा ग्लास को लेकर चिंतित हैं

आजकल बाजार में मेटा चश्मे उपलब्ध हैं, जिनमें लगे लेंस से वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है और सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। स्टिंग ऑपरेशन करने वाले कुछ लोग और पत्रकार ऐसे चश्मे खरीद रहे हैं, लेकिन नेताओं का इनसे डरना स्वाभाविक है। हालांकि हर नेता इन चश्मों से डरता है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि एक व्यवसायी ने मेटा स्मार्ट चश्मे पहनकर उनके और केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशान के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। गुजरात समेत अन्य राज्यों के कुछ मंत्री आगंतुकों से मिलते समय अपने मोबाइल फोन और घड़ियां उतार देते हैं, अब अगर उनसे भी चश्मे उतारने को कहा जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, दिल्ली के कारोबारी दोस्तों, हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपकी बात सुनते हैं। मेट्रो सरकार ने बंद कर दी, सड़कें भी सरकार ने सील कर दीं। सरकार ने राजधानी को भी बंद कर दिया। जब वोट चोरी होते हैं, तो कोई सुरक्षित नहीं रहता। आपकी दुकान, आपकी बचत और आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी से कहिए कि आरोपी नंबर 4 ज्ञानेश कुमार को हटा दें। आंदोलन 30 सेकंड में रुक जाएगा। दिल्ली के व्यापारियों ने मांग की कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली को स्थगित किया जाए। रैली को दिवाली के बाद आयोजित करने की मांग की गई।

अनंत सिंह के बाद, छ्ष्ठ ने उनकी पत्नी नीलम देवी पर भी बड़ा कदम उठाया है। पूर्व मोकामा विधायक नीलम देवी को छ्ष्ठ ने 20 दिवसीय कार्यक्रम समिति से हटा दिया है। इससे पहले, छ्ष्ठ ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। जेडीयू के इशारे पर नीलम देवी को समिति से निष्कासित किया गया है। समिति से नीलम देवी को हटाए जाने के साथ ही उनका उपमंत्री पद भी छीन लिया गया है। ऐसा लगता है कि अब नीलम देवी को सरकार से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। नीलम देवी और उनके पति अनंत सिंह को छह साल से पार्टी से निष्कासित किया गया है। अतीत में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने 2022 में अपनी राजनीतिक विरासत नीलम देवी को सौंप दी थी।

उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों की लहरें हर दिन दोनों दिशाओं में पलट रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में विभिन्न दलों के नेताओं का समाजवादी पार्टी में स्वागत किया।

सिलाई के हुनरः जीवन को सशक्त बनाने का माध्यम, हर टाँका आशा की एक कहानी

सिलाई केवल सुई और धागे से कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण जीवन-कौशल है, जिसमें रचनात्मकता, धैर्य, सटीकता और व्यावहारिक ज्ञान का सुंदर समन्वय होता है। लाखों लोगों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए, सिलाई सशक्तीकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली साधन बन गई है। सिलाई का प्रत्येक टाँका केवल कारीगरी का प्रतीक नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक कदम भी है।

आत्मनिर्भरता की ओर सिलाई का मार्ग- कई समुदायों में आर्थिक तंगी लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के अवसरों को सीमित कर देती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित परिवारों की महिलाओं को सीमित शिक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा रोजगार के कम अवसरों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिलाई उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों के साथ-साथ आय अर्जित करने का व्यावहारिक अवसर प्रदान करती है।

बुनियादी प्रशिक्षण, एक सिलाई मशीन और दृढ़ इच्छाशक्ति के सहारे महिलाएँ कपड़े सिलने, पुराने कपड़ों की मरम्मत करने, स्कूल की वर्दियाँ बनाने तथा घरेलू उपयोग की कपड़े से बनी वस्तुएँ तैयार करने का काम शुरू कर सकती हैं। धीरे-धीरे ये छोटे प्रयास आय के स्थायी स्रोत बन सकते हैं। कुछ महिलाएँ घर से काम करती हैं, जबकि अन्य सिलाई केंद्र, बुटीक या छोटे कपड़ा व्यवसाय स्थापित करती हैं।

ऐसे अवसर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता कम करते हैं और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाते हैं। जब महिलाएँ परिवार की आय में योगदान देती हैं, तो उनके सम्मान, आत्मविश्वास और अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है।

व्यावहारिक कौशल के माध्यम से शिक्षा-शिक्षा हमेशा कक्षा की चारदीवारी तक सीमित नहीं होती। सिलाई जैसे व्यावहारिक कौशल उन लोगों के लिए सीखने के मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते।

सिलाई का प्रशिक्षण एकाग्रता, हाथों और आँखों के बीच समन्वय, माप लेने, समस्याओं का समाधान करने तथा डिजाइन बनाने की क्षमता विकसित करता है। प्रशिक्षु कपड़ों की विभिन्न किस्मों, पैटर्न, रंगों के संयोजन और परिधान निर्माण की तकनीकों के बारे में सीखते हैं। ये गतिविधियाँ रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन को भी प्रोत्साहित करती हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, स्कूल, सामाजिक संस्थाएँ और सामुदायिक संगठन सिलाई की शिक्षा को अधिक लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएँ युवाओं तथा वयस्कों को रोजगार योग्य कौशल प्रदान कर सकती हैं।

जब व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ वित्तीय साक्षरता, डिजिटल मार्केटिंग और उद्यमिता की बुनियादी जानकारी भी दी जाती है, तो लोग अपने कौशल को सफल आजीविका में बदलने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं।

सिलाई मशीन से उद्यमिता तक- एक सिलाई मशीन छोटे व्यवसाय की नींव बन सकती है। शुरुआत में कोई व्यक्ति पड़ोसियों और रिश्तेदारों के कपड़े सिलने के ऑर्डर ले सकता है। अनुभव और ग्राहकों का विश्वास बढ़ने के साथ यह व्यवसाय स्थानीय बाजारों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ सकता है।

मनपसंद डिजाइन के कपड़े, कढ़ाई, कपड़ों की मरम्मत, बच्चों के परिधान, पुनः उपयोग योग्य थैले और घर की सजावट से जुड़ी कपड़े की वस्तुएँ तैयार करना आय के अच्छे अवसर प्रदान करता है। डिजिटल माध्यमों से छोटे उद्यमी अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सकते हैं और दूर-दराज के ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं।

हालाँकि, सफलता के लिए केवल सिलाई का कौशल पर्याप्त नहीं है। काम की गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी, उचित मूल्य, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार और वित्तीय योजना भी आवश्यक हैं। किफायती उपकरण, कच्चा माल, प्रशिक्षण और छोटे ऋण उपलब्ध कराना नए उद्यमियों की सहायता कर सकता है।

सिलाई और सामाजिक परिवर्तन- सिलाई का प्रभाव व्यक्तिगत कमाई तक सीमित नहीं रहता। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तो पूरे परिवार को लाभ होता है। अतिरिक्त आय से बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा के साधन और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

सिलाई समूह और स्वयं सहायता समूह सहयोग तथा आपसी समर्थन की भावना को बढ़ावा देते हैं। महिलाएँ उपकरण साझा कर सकती हैं, सामूहिक रूप से सामग्री खरीद सकती हैं और बड़े ऑर्डर मिलकर पूरे कर सकती हैं। इससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और अकेलेपन की भावना कम होती है।

दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की विशेष कार्रवाई

इन्दौर। दीपावली पर्व के दृष्टिगत आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर द्वारा विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 9 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के 18 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। निरीक्षण के दौरान खराब क्रीम के 2 टीन मौके पर नष्ट कराए गए। खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा वैध खाद्य पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति के अंतर्गत कारोबार संचालित करने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशन में तथा कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में यह अभियान संचालित किया जा रहा है।

विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिए- बालाजी दूध डेयरी एंड स्वीट्स , प्रिंस नगर- प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान प्रोपराइटर श्री विनीत जाट उपस्थित पाए गए। यहां मिठाइयों एवं मावा आदि का निर्माण किया जाना पाया गया। प्रतिष्ठान से मावा एवं मिल्क केक के 2 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।

अजंता स्वीट्स एवं नमकीन, सिरपुर, गोपाल नगर, धार रोड- प्रतिष्ठान के प्रभारी श्री कैलाश त्रिवेदी की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। संचालक को साफ-सफाई बनाए रखने एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। यहां से मिल्क केक का 1 नमूना संग्रहित किया गया, जिसे जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मुसाखेड़ी क्षेत्र की डेयरियों एवं मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई- क्षेत्र में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। महेश दूध डेयरी एवं मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन, मावा एवं पनीर के 3 नमूने, विजय प्रजापत डेयरी एवं स्वीट्स से मिल्क केक एवं मावा के 2 नमूने तथा श्री कृष्णा डेयरी एवं मिष्ठान भंडार से मावा एवं मावा कतली के 2 नमूने लिए गए।

इसी क्रम में यदुराज डेयरी से घी, पनीर एवं मावा कतली के 3 नमूने तथा पालीवाल स्वीट्स से मावा का 1 नमूना जांच हेतु संग्रहित किया गया। यदुराज डेयरी में निरीक्षण के दौरान खराब क्रीम के 2 टीन मौके पर नष्ट कराए गए। श्री कृष्णा डेयरी एवं मिष्ठान भंडार में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

श्री सांवरिया दूध डेयरी एंड स्वीट्स, प्रिंस नगर- कुशवाह नगर चौराहे के पास स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। प्रतिष्ठान के प्रभारी श्री सुभाष यादव की उपस्थिति में मलाई बर्फी एवं मिल्क केक के 2 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।

श्री फलोदी फूड्स, छोटा बांगड़दा- प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर श्री जितेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। परिसर में तिल लड्डू, गुड़ पट्टी, चिक्की, तिल पट्टी एवं राजगीर लड्डू आदि का निर्माण किया जाना पाया गया। यहां से मूंगफली गुड़ पट्टी एवं तिल लड्डू के 2 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। खाद्य पदार्थों के निर्माण के दौरान साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण हेतु आवश्यक वैध खाद्य पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया।

मास्टर प्लान की आरडब्ल्यू-2 सड़क के लिए हटाए अतिक्रमण, 20 हजार वर्गफीट भूमि कराई मुक्त



इन्दौर। इंदौर में मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित आरडब्ल्यू-2 सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा गांधीनगर चौराहे से दिलीप नगर तिराहे के मध्य प्रस्तावित 75 मीटर चौड़ी सड़क के मार्ग में किए गए अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान 6 ढाबे और 4 गुमटियों सहित कुल 10 संरचनाओं को हटाकर लगभग 20 हजार वर्गफीट भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई।

यह कार्रवाई मास्टर प्लान के तहत सड़क निर्माण कार्य को सुगम बनाने और प्रस्तावित मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से की गई। कार्रवाई में राजस्व विभाग, इंदौर विकास प्राधिकरण और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने आपसी समन्वय के साथ कार्य किया।

आबकारी विभाग की कार्रवाई में छह ढाबों से 65 बोतल देशी-विदेशी मदिरा जब्त



इन्दौर। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार तथा सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गत 26 अक्टूबर को आबकारी विभाग की टीम ने विभिन्न ढाबों पर जांच एवं कार्रवाई करते हुए छह स्थानों पर प्रकरण पंजीबद्ध किए।

जिला कंट्रोल रूम प्रभारी श्री कमलेश सोलंकी एवं डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल के निर्देशन में तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री पवन टिकेकर एवं श्रीमती निधि शर्मा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान महाकाल ढाबा, मां भगवती रेस्टोरेंट एवं ढाबा, ठाकुर श्री ढाबा, बाबा ढाबा, राजपूत ढाबा एवं जय मां काली ढाबा जांच की गई। जांच के दौरान इन स्थानों से कुल 65 बोतल देशी एवं विदेशी मदिरा जब्त की गई। संबंधित मामलों में नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।

इसके अतिरिक्त, अवैध मदिरा के परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से हाईवे पर संदिग्ध ट्रकों एवं कंटेनरों की सघन जांच भी की गई। इस दौरान वाहनों की जांच कर अवैध मदिरा के परिवहन सहित अन्य अनियमित गतिविधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कलेक्टर शिवम वर्मा की मानवीय पहल, नेत्रहीन मां के घर का सपना होगा पूरा, कैंसर पीड़िता को मिलेगी उपचार में मदद

इन्दौर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं।

कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रत्येक प्रकरण की स्थिति और आवेदकों की आवश्यकताओं को समझते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर उनका त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जनसुनवाई आमजन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं और प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि



नागरिकों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें समय पर राहत प्रदान की जाए।

जनसुनवाई में श्रीमती राखी जोशी ने कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए बताया कि वे दोनों आंखों से नेत्रहीन हैं और अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहती हैं। उनका तलाक हो चुका है तथा परिवार में सहयोग के लिए कोई नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें जीवनयापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण आवास क्रय करने में परेशानी आ रही है। उनकी समस्या को संवेदनशीलता से सुनते हुए कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने जरुरी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि शासन-प्रशासन जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और हरसंभव सहयोग प्रदान किया जायेगा।

जनसुनवाई के एक अन्य प्रकरण में श्रीमती रामकन्या बाई (परिवर्तित नाम) ने कलेक्टर श्री शिवम वर्मा को बताया कि वे लंबे समय से ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें उपचार कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर श्री वर्मा ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए 15 हजार रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही, उनके उपचार के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, ताकि उन्हें समय पर उपचार संबंधी मदद मिल सके।

ब्राह्मण समाज 30 अक्टूबर को लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा में होगा शामिल

इंदौर। सर्व ब्राह्मण युवा संगठन की ओर से आयोजित प्रबुद्धजनों की संगोष्ठी में 30 अक्टूबर को प्रस्तावित 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा में पूरी ताकत से शामिल होने का संकल्प लिया गया। संगोष्ठी में प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से देश की वर्तमान परिस्थितियों, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे।



संगोष्ठी में राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्थिरता को सर्वोपरि बताते हुए सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने विदेशी शक्तियों के कथित हस्तक्षेप और देश की आंतरिक स्थिरता को प्रभावित करने वाली चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित, संवैधानिक व्यवस्था और सामाजिक समरसता के प्रति जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है।

चर्चा में विश्व के विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई। साथ ही, समाज के प्रबुद्ध वर्ग से तथ्यों और विवेक के आधार पर जनजागरण करने तथा राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट सहित बड़ी संख्या में संगठन के विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारीगण, ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित थे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पं. योगेंद्र महंत ने की। संचालन पं. दिनेश दवे ने किया, जबकि आभार पं. दिनेश शर्मा ने माना। कार्यक्रम की व्यवस्था पं. मनोज मिश्रा और पं. राजेश हार्दोनिया ने संभाली। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अन्य अतिथियों का स्वागत सर्व ब्राह्मण युवा संगठन के पदाधिकारियों एवं विभिन्न इकाइयों के अध्यक्षों ने किया।

सर्व ब्राह्मण युवा संगठन की केंद्रीय इकाई के अध्यक्ष पं. संदीप जोशी ने संगोष्ठी में शामिल वरिष्ठजनों, प्रबुद्ध नागरिकों और समाजबंधुओं के प्रति आभार व्यक्त किया तथा समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा में शामिल होने का आवाहन किया।

सर्व ब्राह्मण युवा संगठन, महालक्ष्मी नगर इकाई के संरक्षक पं. के.के. झा ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों में जागरूकता, संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को तथ्यों और विवेक के आधार पर जनजागरण करते हुए राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

डबलडेकर फ्लाईओवर से इंदौर-उज्जैन का सफर सिर्फ 40 मिनट में होगा तय, सिंहस्थ में रोज तेजी से गुजरेंगे 4 लाख वाहन

इंदौर। इंदौर में बने डबलडेकर से सिंहस्थ में रोजाना लाखों वाहन गुजरेंगे। सिंहस्थ के समय इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से इंदौर आने वाले वाहनों की संख्या करीब 4 लाख हो सकती है। ऐसे में इस ब्रिज से इंदौर से उज्जैन की दूरी सिर्फ 40 मिनट में पूरी हो जाएगी।

डबलडेकर बनने से वाहनों की आवाजाही सरपट हो गई है। जल्द ही दूसरी भुजा पर भी ट्रैफिक होगा, जिससे इंदौर से उज्जैन जाने वालों को राहत मिलेगी। इंदौर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल लवकुश चौराहा सबसे आधुनिक ट्रैफिक इंटरचेंज के रूप में विकसित हो रहा है। यहां करीब 175 करोड़ रुपए की लागत से बने डबलडेकर की एक भुजा पर तो ट्रैफिक चल रहा है।

कम होगा ट्रैफिक का दबाव- देखा जाए तो एमपी का पहला ऐसा डबलडेकर ब्रिज है, जहां रोड, ब्रिज, मेट्रो एक ही कॉरिडोर



(एमआर-10) पर अलग-अलग स्तर पर संचालित हो रहे हैं। नीचे रोड पर ट्रैफिक और मेट्रो ट्रैक। सीमित जगह में दोहरी परिवहन व्यवस्था डेवलप होने से आने वाले दिनों में ट्रैफिक का दबाव भी कम होने का अनुमान है।

इतनी गाड़ियों का दबाव संभालने की तैयारी- आम दिनों में इंदौर-उज्जैन मार्ग से रोजाना 35 से 40 हजार वाहन गुजरते हैं, जबकि सावन में यह संख्या 70 से 80 हजार से अधिक हो जाती है। सिंहस्थ के दौरान वाहनों की संख्या करीब 4 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।

2016 के सिंहस्थ के आखिरी शाही स्नान पर इंदौर-सांवेर रोड से हरिफाटक तक लंबा जाम लगा था। वाहन चालक घंटों फंसे रहे थे। इस बार डबलडेकर ब्रिज से लवकुश चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और इंदौर-उज्जैन मार्ग पर आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को मिलेगी गति- राज्य सरकार इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन (ढ्रस्क्र) विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य दोनों शहरों को आर्थिक, औद्योगिक, आवासीय और परिवहन नेटवर्क के रूप में जोड़ना है। लवकुश डबलडेकर ब्रिज इस कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली अहम कड़ी बन सकता है। बेहतर सड़क नेटवर्क और मेट्रो कनेक्टिविटी से भविष्य में औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

2023 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट- IDA ने साल 2023 में इस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कराया था। मेट्रो कॉरिडोर के साथ समन्वय, तकनीकी जटिलताओं और स्टील बो-स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के निर्माण के कारण काम कई चरणों में पूरा किया गया। पहली लेन 23 जुलाई को शुरू हुई वहीं दूसरी लेन भी जल्द शुरू जाएगी।

भोपाल के रीजनल सरस मेले में इंदौर की मीना दीदी के लेदर टॉय की धूम

केलोद हाला के शारदा स्वयं सहायता समूह ने लगाई स्टॉल, तीन दिन में 10 हजार रुपये की सामग्री का विक्रय



इन्दौर। राजधानी भोपाल में आयोजित रीजनल सरस मेले में इंदौर जिले के विकासखंड इंदौर के ग्राम केलोद हाला के शारदा स्वयं सहायता समूह की मीना दीदी द्वारा निर्मित लेदर टॉय की स्टॉल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मेले के शुरुआती तीन दिनों में ही स्टॉल से लगभग 10 हजार रुपये की सामग्री का विक्रय हो चुका है। यह उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाती है।

इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आजीविका से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को अपने कौशल के अनुरूप उत्पाद तैयार करने, उन्हें बाजार उपलब्ध कराने और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रीजनल सरस मेला ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। मीना दीदी द्वारा तैयार किए गए लेदर टॉय जैसे हस्तनिर्मित उत्पादों को इस मंच के माध्यम से व्यापक बाजार तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। इससे न केवल समूह की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के हुनर को नई पहचान भी मिल रही है।

शारदा स्वयं सहायता समूह की यह पहल महिला सशक्तीकरण, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण है।

शक्ति के पर्व पर 300 बालिकाओं का सम्मान, समाजसेवियों को किया पुरस्कृत



इंदौर। मां मनसा देवी भगवती कृपा रुप द्वारा सियागंज चौराहे पर भजन संध्या,शक्ति सम्मान समारोह, पुरस्कार वितरण एवं कन्या भोज, भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 300 बालिकाओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। महिला अखाड़े की कलाकारो के साथ अलग अलग क्षेत्रों में गरबा करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार से साथ ही समाजसेवा एवं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों का सम्मान किया गया।

आयोजन समिति के अध्यक्ष कैलाश श्रीवास्तव, संयोजक हरीश राठौर (लड्डू बाबा) ने बताया कि समारोह में महिला अखाड़े की संचालक हेमलता बौरासी, समाजसेवी धर्मेंद्र राठौर, अशोक शुक्ला, विपलव अग्रवाल राजेश यादव , राजेश मालविय का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गजासिन शनि धाम के दादू महाराज ने जल संरक्षण का संदेश देते हुए सभी से पानी बचाने और इसके प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का सफल संचालन गोविंद राठौर (राठौर क्रांति) ने किया। आभार पूनम गोयल ने माना।

संक्षिप्त समाचार

सिहावल में आज से सजेगा श्रीरामलीला उत्सव का मंच

सीधी। मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन सीधी के सहयोग से सिहावल में 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पांच दिवसीय श्रीरामलीला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। लोहा देवी मंदिर, मायापुर स्टेडियम में प्रतिदिन शाम 7 बजे से श्रीरामकथा के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित लीलाओं का मंचन होगा। आयोजन में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। उत्सव के पहले दिन 29 अक्टूबर को शंकर विवाह, श्रीराम जन्म, ताड़का वध और अहिल्या उद्धार के प्रसंगों का मंचन किया जाएगा। 30 अक्टूबर को धनुष यज्ञ, श्रीराम विवाह, वनगमन और केवट प्रसंग प्रस्तुत होंगे। 31 अक्टूबर को दशरथ देवलोक गमन, भरत मिलाप और सीता हरण की लीलाएं होंगी। वहीं, 1 नवंबर को शबरी प्रसंग, श्रीराम-सुग्रीव मैत्री और लंका दहन का मंचन किया जाएगा। उत्सव के अंतिम दिन 2 नवंबर को लंका युद्ध, रावण वध और श्रीराम राज्याभिषेक की प्रस्तुतियों के साथ आयोजन का समापन होगा। श्रीरामलीला उत्सव के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों, आदर्शों और मर्यादा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के साथ भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। आयोजन में श्रीरामलीला लीला गुरुकुल संस्थान द्वारा विशेष रूप से परिकल्पित प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आलेख योगेश त्रिपाठी (रीवा), संगीत संयोजन सीताराम सिंह (पटना) तथा लीला निर्देशन रामचन्द्र सिंह (भोपाल) का रहेगा।

अघोषित बिजली कटौती तुरंत बंद हो-अजय सिंह

सीधी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने चुरहट विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे इलाके में जारी भारी अघोषित बिजली कटौती को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस समय पूरे चुरहट क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती चरम पर है। लोड शेडिंग के नाम पर कई-कई घंटों तक



बिजली काटी जा रही है, जिससे जनता का जीना दूभर हो गया है। बिजली कोई विलासिता नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है, इसलिए चुरहट की जनता को इस तरह अंधेरे में रखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजय सिंह ने कहा कि बिजली की इस आंख-मिचौली से समाज का हर वर्ग बुरी तरह प्रभावित है। अघोषित कटौती के कारण बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। खेतों में सिंचाई के लिए बिजली न मिलने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं।

अवैध रेत सहित दो हाइवा जप्त

सीधी। उप संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी राजेश कन्नाटी के निर्देशन व अधीक्षक सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी प्रमोद सिंह के नेतृत्व में 27-28 अक्टूबर की दरम्यानी रात मुखबिर से प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए परिक्षेत्र सोन घड़ियाल अभ्यारण्य रामपुर नैकिन अंतर्गत बीट घोंघी के सोन नदी झिरिया घाट से रेत का अवैध उत्खनन/परिवहन करते दो वाहन हाइवा बिना नंबर प्लेट के जप्त कर विभिन्न धाराओं में वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर सुरक्षार्थ काष्ठागार जमोड़ी में खड़ा कराया गया।

लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' संगोष्ठी

प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में राष्ट्रहित, लोकतंत्र व नक्सलवाद के उन्मूलन पर मंथन

सीधी (ब्यूरो)



भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली की विधानसभा स्तरीय 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' विषय पर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सामुदायिक भवन बैढ़न में आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्र की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, नक्सलवाद के उन्मूलन तथा देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए समाज में जनजागरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया।

संगोष्ठी मे समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों की उपस्थिति रही तथा उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में बुद्धिजीवी वक्ताओं वर्तमान परिवेश में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। विपक्ष द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मूल्यों को दरकिनार कर भ्रामकता तथा अराजकता फैलाने के कृत्यों की निंदा की गई। बुद्धिजीवियों ने संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्षियों के दिशाहीन आरोपों की भी निंदा की। देश की युवा पीढ़ी को बाहरी शक्तियों और राष्ट्र को अस्थिर करने वाली उनकी नकारात्मक नैरेटिव से बचने की सलाह दी गई।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह ने कहा कि देश में अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध जनजागरण आवश्यक है। उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती पर बल दिया। सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने अपने उद्बोधन में देश की वर्तमान परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयास देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण हैं।

समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

- बैरीकेट्स तोड़ने के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का किया उपयोग

सीधी (ब्यूरो)

जिले के युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष करुण सिंह चौहान के नेतृत्व में अस्पताल की व्यवस्था सहित भाजपा सरकार के खिलाफ जबरजस्त आंदोलन रहा। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। कांग्रेसी युवा नेताओं द्वारा जब बैरीकेट्स तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में जाने लगे तो उस दौरान रोंकने के लिए प्रशासन द्वारा वाटर कैनान का उपयोग किया गया। इसके बाद गिरफ्तारी भी की गई, बाद में छोंड़ दिया गया।

जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं, स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी और सीधी मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही देरी के विरोध में जिला युवा कांग्रेस ने बुधवार को कलेक्ट्रेट घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग उठाते हुए शासन-प्रशासन का ध्यान जिले की गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक परमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष करुण सिंह चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को प्रमुखता से उठाया।



संजय गांधी कॉलेज के 200 विद्यार्थियों ने ली नशामुक्ति की शपथ

सीधी (ब्यूरो)



नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन एवं उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सीधी के मार्गदर्शन में संजय गांधी कॉलेज में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के 200 विद्यार्थियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थियों ने स्वयं नशे से दूर रहने और समाज में नशामुक्ति का संदेश प्रसारित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शिवांशु शुक्ला, विशेष शिक्षक डीडीआरसी, पुष्पेंद्र शुक्ला, मैनेजर डीईआईसी एवं स्वाती सिंह, दंत चिकित्सक ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशे की लत व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा अपने परिवार, मित्रों एवं समाज के अन्य लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी 200 विद्यार्थियों ने नशामुक्त जीवन अपनाने तथा नशामुक्त भारत के निर्माण में सहयोग देने की शपथ ली।

प्रभावित ग्रामीणों ने मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर किया धरना-प्रदर्शन

- टीएचडीसी कं. पर मनमानी का आरोप

सीधी (ब्यूरो)

जिले की अमिलिया स्थित टीएचडीसी कोल माइंस प्रबंधन के मनमानी रवैए व वादाखिलाफी के खिलाफ तथा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को मोर्चा खोल दिया। इस कोल माइंस से प्रभावित विस्थापितों और प्रभावित सैकड़ों ग्रामीण कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने धरना पर बैठ गये जिससे पूरे दिन कामकाज प्रभावित रहा और दर्जनों कर्मचारियों का आना-जाना बंद रहा।

विस्थापितों के गंभीर आरोप - विस्थापितों ने टीएचडीसी कंपनी प्रबंधन पर मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया है। विस्थापितों का आरोप है कि वर्ष 2017 से कंपनी कोयला उत्खनन का काम कर रही है। उनके जमीन और मकान ले लिए हैं। बावजूद इसके उन्हें विस्थापन का पूरा लाभ नहीं मिला है। तेंदुआ गांव के सरपंच छोटेलाल मरावी ने बताया कि करीब 270 लोगों को अब तक विस्थापन का पूरा लाभ नहीं मिला है। 95 वर्षीया बुजुर्ग महिला राजमंति देवी ने बताया कि उनकी 85 एकड़ जमीन और मकान चले गए, लेकिन कंपनी प्रबंधन की ओर से जारी विस्थापितों की सूची में उनका नाम ही नहीं है। कंपनी प्रबंधन का पक्ष इस खबर में शामिल नहीं है।



सिंगरौली जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी कंपनियों की परियोजनाओं तथा उनके विस्तार से प्रभावित विस्थापित परिवारों को संपूर्ण पुनर्वास लाभ, सही मुआवजा और रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी मंगलवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। बसपा जिलाध्यक्ष व पार्षद ननि सिंगरौली वार्ड नं 7, शिवशंकर प्रसाद, सुरेश शाहवाल और वंशरूप शाह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रभावित गांवों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है।

दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई तो मझौली लोक सेवा केंद्र में होगी तालाबंदी

सीधी (ब्यूरो)

लोक सेवा केंद्र मझौली में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पाण्डेय ने जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। विवेक पाण्डेय ने आरोप लगाया कि पूर्व जिला कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी एवं एसडीएम मझौली के कार्यकाल में जांच के दौरान संबंधित संचालक को दोषी पाया गया था। विवेक पाण्डेय ने कलेक्टर से पूर्व आदेशों का पालन कराने, निष्पक्ष वित्तीय जांच करने और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो शिवसेना मझौली लोक सेवा केंद्र में तालाबंदी करने के लिए बाध्य होगी।

इस बीच प्रमुख रूप से शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पाण्डेय, जिला अध्यक्ष बेनाम सिंह बघेल, जिला उपाध्यक्ष हृदय त्रिवेदी उर्फ हेतु, नगर अध्यक्ष जैनेंद्र सिंह चौहान उर्फ मुन्ना, अनिल केवट, सुनील सिंह मझौली तलवारी, रामकुमार कोल मौजूद रहे।

युवा संगम रोजगार मेले में 60 युवाओं का प्रारंभिक चयन



सीधी (ब्यूरो)

मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार एवं जिला प्रशासन के निर्देशन में जिला रोजगार कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आईटीआई सिंगरौली के संयुक्त तत्वावधान में विगत दिवस अटल सामुदायिक भवन, बिलौंजी में विकासखंड स्तरीय 'युवा संगमङ्करोजगार, स्वरोजगार एवं प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला' आयोजित किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघप्रिय के मार्गदर्शन में आयोजित मेले का उद्देश्य जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें स्वरोजगार एवं कौशल विकास की योजनाओं से जोड़ना रहा। रोजगार मेले में जिले के बड़ी संख्या में युवक-युवतियों ने सहभागिता कर विभिन्न निजी कंपनियों में रोजगार के लिए आवेदन किया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आवेदकों की योग्यता एवं पात्रता के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की। मेले में शामिल 10 प्रमुख कंपनियों के माध्यम से 41 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया, जिनमें 4 महिला आवेदक शामिल हैं। वहीं, युवा संगम के अंतर्गत रोजगार, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना एवं अप्रेंटिसशिप के लिए 19 अन्य आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया।

श्री श्याम प्रेमी मंडल के चतुर्थ वार्षिकोत्सव 22 नवंबर को

सीधी (ब्यूरो)

श्री श्याम प्रेमी मंडल जिला सिंगरौली के चतुर्थ वार्षिकोत्सव 22 नवंबर 2026, रविवार को विंध्यनगर स्थित मेला ग्राउंड में श्री श्याम बाबा का जन्मोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। शाम 5:15 बजे से शुरू होने वाले इस धार्मिक आयोजन में भव्य श्याम दरबार, संगीतमय भजन संध्या, छप्पन भोग और श्रद्धालुओं के लिए श्याम रसोई की व्यवस्था रहेगी।

यह रहेंगे आकर्षण के बिंदु - आयोजन का मुख्य आकर्षण मथुरा के गोयल डेकोर द्वारा तैयार किया जाने वाला श्री श्याम बाबा का फूलों की मनमोहक व विशेष साज-सज्जा से सुसज्जित दरबार आकर्षण का केंद्र रहेगा। पूरे आयोजन को भक्तिमय वातावरण में संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है।

भजन संध्या के कलाकार - भजन संध्या में दिल्ली की ट्विंकल शर्मा, अयोध्या के श्रवण सुल्तानपुरी, रेनुकूट के कृष्णा शर्मा, छतरपुर की प्रतिमा सिंह परमार और स्थानीय भजन गायिका अनुष्का पाण्डेय अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से बाबा श्री श्याम का गुणगान करेंगे।

एमपी टूरिज्म क्विज में सीधी का प्रदेश में तीसरा स्थान



सीधी (ब्यूरो)

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज-2026 में सीधी जिले की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है।

सीधी के काशी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की टीम ने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का परिचय देते हुए जिले का गौरव बढ़ाया। भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में प्रदेश के छह जिलों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें बालाघाट की टीम प्रथम, धार की टीम द्वितीय और सीधी की टीम तृतीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता में प्रदेश के 53 जिलों से 24 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने सहभागिता की।

सीधी की टीम को मिलेगा निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का अवसर

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सीधी की टीम को मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए तीन दिन और दो रात का निःशुल्क टूर पैकेज प्रदान किया गया है। इसके तहत विद्यार्थियों को पर्यटन विभाग के अंतर्गत आने वाले होटलों में ठहरने और प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा।

प्रभावितों की समस्याओं के लिए मिला आश्वासन

- शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न पर्यावरणीय जनसुनवाई

सीधी (ब्यूरो)

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की खड़िया खुली खदान (ओसीपी) के विस्तारीकरण हेतु 28 अक्टूबर 2026 को स्थानीय डीएवी स्कूल खेल मैदान में आयोजित पर्यावरणीय लोक सुनवाई सफल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। यह महत्वपूर्ण बैठक अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रमेश चंद्र और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सोनभद्र) के क्षेत्रीय अधिकारी आर.के. सिंह की संयुक्त



अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम में जिला प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एनसीएल प्रबंधन के प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और विस्थापित परिवार उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान अधिकारियों और प्रबंधन ने परियोजना के विस्तार की तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया। प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया कि खदान के इस विस्तार से राष्ट्रीय स्तर पर कोयला आपूर्ति सुदृढ़ होगी और स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

शिकायतों पर अधिकारियों का पक्ष- कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी लिखित शिकायतें और मांगें अधिकारियों के समक्ष रखीं। इस पर खदान प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक (उत्खनन) वी.के. राय, सीएसआर नोडल अधिकारी अमरेन्द्र कुमार और पर्यावरण अधिकारी रोहित गुप्ता ने ग्रामीणों की शिकायतों का सिलसिलेवार जवाब दिया और समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने का पूरा आश्वासन दिया।

इस अवसर पर खदान प्रबंधन की तरफ से खड़िया परियोजना के महाप्रबंधक के.डी. जैन, परियोजना अधिकारी (पीओ) आर.के. अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

नगर परिषद बरगवां ने की अतिक्रमण हटाने की पहल

सीएमओ ने व्यापारियों के साथ बैठक कर किया संवाद

सीधी (ब्यूरो)

इसी क्रम में दिनांक 28 अक्टूबर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवसर शुसीर श्री कृष्ण श्रीराम और सीएमओ अमित सिंह द्वारा नगर परिषद बरगवां के बाजार क्षेत्र एवं अतिक्रमण प्रभावित स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क एवं नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण से उत्पन्न समस्याओं को संज्ञान में लिया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस संबंध में नगर परिषद द्वारा सभी प्रकार के व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित कर संवाद किया गया। बैठक में व्यापारियों को सार्वजनिक सड़कों, नालियों एवं शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने तथा बाजार क्षेत्र को व्यवस्थित बनाए रखने के संबंध में समझाइश दी गई।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी नगर परिषद द्वारा संबंधित व्यक्तियों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में व्यापारियों की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसी विषय को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी, देवसर के निर्देशानुसार संबंधित अतिक्रमणकारियों को पुनः अंतिम नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को 7 दिवस के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाकर नगर परिषद कार्यालय को लिखित रूप में सूचित करना होगा।



सांदीपनि विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अधूरा

सीधी (ब्यूरो)

विकासखंड चितरंगी में शासकीय सांदीपनि विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य को जनवरी 2026 तक पूर्ण कर सौंपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके बावजूद भवन का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा है। निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर अब जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है।



जानकारी के अनुसार, तत्कालीन कलेक्टर गौरव बैनेल के निरीक्षण के दौरान संविदाकार द्वारा मई 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने की बात कही गई थी। लेकिन अक्टूबर 2026 बीतने को है और अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इससे निर्माण की गुणवत्ता, कार्य की गति और निर्धारित समय सीमा के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

दो तरफ की बाउंड्रीवॉल अधूरी, फिनिशिंग भी बाकी

विद्यालय भवन एवं छात्रावास के निर्माण के साथ परिसर के चारों ओर बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया जाना है। वर्तमान स्थिति यह है कि बाउंड्रीवॉल का कार्य दो तरफ अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा भवन की फिनिशिंग का काम भी पूरा नहीं हुआ है।

PNB ग्राहकों के लिए बुरी खबर! 10 नवंबर के बाद बंद हो जाएंगे ये अकाउंट, तुरंत निपटाएं जरूरी काम



नई दिल्ली (एजेंसी)। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। बैंक ने उन ग्राहकों के लिए एक जरूरी नोटिस भेजा है जिन्होंने पिछले तीन साल से अपने खाते का इस्तेमाल नहीं किया है, साथ ही जिनका बैंक बैलेंस भी तीन साल जीरो है। बैंक के हिसाब से ये कदम खातों के गलत इस्तेमाल को रोकने और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उठाया गया है। आइए जानते हैं बैंक ने नोटिस में क्या-क्या कहा।

किन खातों पर गिरेगी गाज- बैंक की ओर से दिए गए नोटिस के हिसाब से उन खातों को बंद कर दिया जाएगा जिनमें 30 सितंबर 2026 तक पिछले 3 साल या उससे ज्यादा समय से कोई भी ग्राहक-प्रेरित ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और जिन खातों का बैंक बैलेंस जीरो है। ऐसे में बैंक उन सभी लोगों को 10 नवंबर 2026 तक का समय दिया है, ताकी वो तब तक खाते को फिर से एक्टिव कर लें। क्या कदम उठाना होगा?

अगर आप चाहते हैं कि आपका खाता बंद न हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा-

केवाईसी पूरी करें- अपने खाते को दोबारा चालू कराने के लिए आपको अपनी होम ब्रांच में जाकर केवाईसी से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे।

ब्रांच में करें संपर्क- बैंक जाने से पहले अपनी ब्रांच में फोन करके यह जरूर पता कर लें कि आपको कौन-कौन से दस्तावेज साथ ले जाने हैं, ताकि बार-बार चक्कर न काटने पड़ें। साथ ही यह भी कंफर्म कर लें कि आपका खाता इस दायरे में आता है या नहीं।

अगर आपके मन में खाते से जुड़ी कोई और भी समस्या है तो आप बैंक के टोल-फ्री नंबर (1800-1800 और 1800-2021) पर भी कॉल कर सकते हैं। वहीं बैंक की ओर से किसी भी तरह की अफवाह से बचने के लिए साफ कहा गया है, ताकि कोई और आपका या आपके खाते का इस्तेमाल गलत तरीके से न कर पाए।

खाड़ी देशों में फिर बढ़ेगी भारतीय बासमती की मांग! मंडियों में भी बढ़े दाम; किसानों और एक्सपोर्टर्स की चांदी



नई दिल्ली (एजेंसी)। इस साल जलवायु कारणों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की सप्लाई और बढ़ती कीमतें चिंता का कारण बन रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय निर्यातकों और किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इस साल भारत में बासमती चावल की पैदावार पिछले साल के मुकाबले 5 से 10त्न तक बढ़ने का अनुमान है। बासमती ढ्ढश्रश्व के अध्यक्ष चमन लाल सेतिया और ज्वाइंट स्ख्ड राजीव सेतिया के मुताबिक बेहतर मानसून और बासमती फसल के अनुकूल मौसम के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है।

नई दिल्ली में 23 से 25 अक्टूबर तक आयोजित भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में सेतिया ने कहा कि मानसून और उसके बाद हुई अच्छी बारिश से बासमती की फसल को फायदा मिला है। इससे इस साल पैदावार बेहतर रहने की उम्मीद है। इसी वजह से इस साल बासमती चावल की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में 5 से 10त्न अधिक रहने की संभावना है। विदेशी बाजारों में बढ़ रही मांग- भारतीय बासमती चावल पहले ही कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बना चुका है। इस साल की शुरुआत से ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चल रही उथल-पुथल के कारण भारतीय बासमती की शिपमेंट और सप्लाई में समस्याएं आई हैं। क्योंकि खाड़ी देश भारतीय बासमती के प्रमुख खरीदार हैं। राजीव सेतिया ने भारतीय बासमती चावल की मांग को लेकर भी उम्मीद जताई। उनके मुताबिक, आने वाले समय में बासमती की मांग बढ़ने की संभावना है। भारतीय बासमती पहले ही कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बना चुका है। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी 96 देशों में चावल का निर्यात करती है। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका में भारतीय खानपान की लोकप्रियता बढ़ रही है। इससे पारंपरिक बाजारों के अलावा दूसरे देशों में भी बासमती चावल की मांग बढ़ने की संभावनाएं हैं। सेतिया ने ग्लोबल मार्केट में भारतीय बासमती की पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि इसे भौगोलिक संकेतक यानी ज्ञ्ढ्ढ की मान्यता मिली हुई है और इसकी खेती निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों में की जाती है। एक्सपोर्ट के लिए बेहतर मौका भारत दुनिया के प्रमुख बासमती उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। बासमती चावल देश के कृषि निर्यात में अहम योगदान देता है। इस साल पैदावार बढ़ने से निर्यात के लिए चावल की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। जानकारों का कहना है कि इससे निर्यातकों के साथ ही बासमती किसानों की भी आय बढ़ेगी, मंडियों में भी दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि, निर्यात में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग, कीमतों और व्यापार की परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।

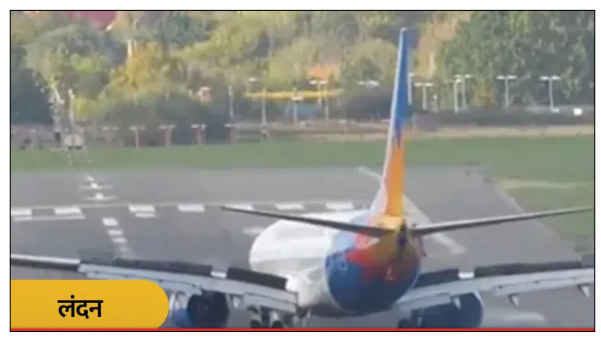
जर्मनी में युवक ने भीड़ पर जानबूझकर चढ़ाई तेज रफ्तार BMW कार, 5 लोग घायल



नई दिल्ली (एजेंसी)। सोमवार को देर रात उत्तरी जर्मनी में एक कार ने जानबूझकर लोगों के समूह को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हो गए।

पुलिस ने मामले की दी जानकारी- पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि न्यूस्टैड एम रूबेनबर्गे में एक क्रूद्ध कार को आरोपी ने जानबूझकर लोगों के एक समूह पर चढ़ा दिया।

बर्मिंघम एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे पर फिसला Jetw बोइंग विमान



नई दिल्ली (एजेंसी)। ब्रिटेन के बर्मिंघम एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया। इटली के वेनिस से आ रहा जेट 2 एयरलाइंस का एक एक बोइंग 737-800 विमान रनवे पर उतरते समय तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते असंतुलित होकर घास की तरफ फिसल गया।

हालांकि पायलट की सूझबूझ से विमान तुरंत वापस रनवे पर आ गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन विमान के असंतुलित होने के का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

हवा के तेज झोंके से बिगड़ा विमान का संतुलन- BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना स्ख्1310 के साथ हुई, जो वेनिस के मार्को पोलो एयरपोर्ट से बर्मिंघम पहुंची थी।

वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि टचडाउन के बाद ट्विन-जेट विमान अचानक बाईं तरफ मुड़ गया। संतुलन बिगड़ने के कारण विमान का एक पहिया रनवे छोड़कर किनारे मौजूद घास वाले हिस्से पर चला गया।

हालांकि कुछ ही सेकेंड के अंदर विमान के संतुलन को वापस साध लिया गया और वह टैरमैक पर लौट आया। विमान को सुरक्षित रूप से टैक्सी कर स्टैंड तक लाया गया, जहां से सभी यात्रियों को बिना किसी चोट के सकुशल बाहर निकाला गया।

बोएलो तूफान का दिखा असर- जेट2 एयरलाइंस के प्रवक्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, वेनिस से बर्मिंघम आ रही फ्लाइट स्ख्1310 लैंडिंग के बाद बोएलो तूफान के कारण बने गंभीर मौसमी हालात के चलते कुछ पलों के लिए रनवे से बाहर चली गई थी। विमान तुरंत रनवे पर लौट आया और सामान्य रूप से स्टैंड तक पहुंचा। हम पुष्टि करते हैं कि सभी यात्री सुरक्षित हैं।

एयरलाइव की रिपोर्ट के अनुसार, लैंडिंग के समय इलाके में हवा की रफ्तार करीब 54 किमी/घंटा दर्ज की गई थी।

यूके में बोएलो तूफान का कहर

यूके मेट ऑफिस के अनुसार, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के इलाकों में 60 से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं।

खुले और तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 129 किमी/घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। खुले और तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 129 किमी/घंटा तक पहुंचने का अनुमान है।

मेट ऑफिस के डिप्टी चीफ फोरकास्टर क्रिस बुलमर ने बताया कि बोएलो तूफान के असर से देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश के साथ तेज अंधड़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे हवाई और रेल यातायात पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

युगांडा में 15 साल में 38 लोगों को मारकर खा गया नरपिशाच, आर्मी चीफ बोले- मौत की सजा देंगे



नई दिल्ली (एजेंसी)। युगांडा के सुरक्षा बलों ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर पिछले 15 वर्षों के दौरान 38 लोगों की हत्या कर उनका मांस खाने का गंभीर आरोप है।

देश के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के जनरल मुहूजी काइनेरुगाबा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर गिरफ्तारी की जानकारी दी है।आरोपी की पहचान मुजुरिजी मोसेस के रूप में हुई है, जिस पर 2010 से 2025 के बीच मसाका, इबांडा और काजो जिलों में जघन्य अपराधों को अंजाम देने का आरोप है।

सैन्य प्रमुख ने क्या कहा- जनरल काइनेरुगाबा ने आरोपी को युगांडा के इतिहास का सबसे क्रूर सीरियल किलर और आदमखोर करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुरक्षा बलों ने मुजुरिज़ी मोसेस को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

उन्होंने कहा कि आरोपी ने 15 वर्षों में 38 लोगों को मौत के घाट उतारा और उनका मांस खाया। सैन्य प्रमुख ने यह भी कहा कि आरोपी पर अदालत में खुला और सार्वजनिक मुकदमा चलाया जाएगा और उसे मौत की सजा दिलाई जाएगी।

हत्या करने का खौफनाक तरीका- जांचकर्ताओं के अनुसार, मोसेस बेहद क्रूरता से वारदातों को अंजाम देता था। वह अक्सर पूरे-पूरे परिवारों को निशाना बनाता था, रात में घरों में घुसकर धारदार हथियारों से लोगों पर हमला करता था। उसके गिरोह ने कथित तौर पर पादरी स्टीवन मुगाम्बे के घर की दीवार काटकर अंदर प्रवेश किया और घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी।

कुछ अन्य मामलों में, आरोपी पर यह भी आरोप है कि वह लोगों को प्रेम प्रसंग या संबंधों का झांसा देकर फंसाता था और बाद में उनकी हत्या कर देता था।

पहले भी कई बार बच निकला था आरोपी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोसेस को पूर्व में भी कई बार पकड़ा गया था, लेकिन विवादित परिस्थितियों में वह या तो हिरासत से भाग निकला या रिहा हो गया। ताजा गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसके ठिकाने से अहम भौतिक साक्ष्य बरामद किए हैं।

स्थानीय पुलिस और जांच अधिकारी अब इलाके के कई पुराने अनसुलझे मामलों, हत्या की फाइलों और लापता लोगों के रिकॉर्ड की दोबारा पड़ताल कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे मामले भी इसी आरोपी से जुड़े हैं।

हालांकि, आरोपी पर लगाए गए इन सभी आरोपों की पुष्टि कानूनी प्रक्रिया और अदालत की सुनवाई के जरिए ही तय होगी।

वीटो का इस्तेमाल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, UN में भारत की दो टूक

नई दिल्ली (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में व्यापक सुधारों की अपनी मांग को एक बार फिर दोहराते हुए भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (पी5) को मिला वीटो पावर का विशेषाधिकार किसी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को साधने का साधन नहीं बनना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थवनेनी हरीश ने देश का पक्ष रखते हुए कहा कि वीटो केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मसलों पर वीटो का इस्तेमाल बेहद संयम के साथ किया जाना चाहिए। वीटो के अंधाधुंध इस्तेमाल से सुरक्षा परिषद की साख को नुकसान- भारतीय राजदूत ने वीटो के ऐतिहासिक इस्तेमाल का ब्योरा देते हुए बताया कि कुछ चुनिंदा देशों द्वारा इसके असंतुलित उपयोग ने सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है।

इजरायल में मतदान, संसद में एंट्री के लिए 3.25% वोट जरूरी



नई दिल्ली (एजेंसी)। इजरायल में 27 अक्टूबर, मंगलवार को आम चुनाव होना है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड और उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के बीच माना जा रहा है।

इजरायल के 73 लाख मतदाता कल तय करेंगे कि देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में बरकरार रहेंगे या नहीं। आइए जानते हैं इजरायल में कैसे होता है चुनाव और कैसे काम करती है वहां की चुनावी राजनीति और गठबंधन का गणित।

दरअसल, इजरालय में संसद की कुल 120 सीटें और करीब 73 लाख मतदाता हैं। इजरायल में पूरी चुनावी प्रक्रिया एक देश, एक निर्वाचन क्षेत्र की आनुपातिक प्रणाली पर चलती है।

संसद में एंट्री के लिए 3.25त्न वोट पाना अनिवार्य- यहां मतदाता उम्मीदवार के बजाय पार्टी लिस्ट को वोट देते हैं और संसद में प्रवेश के लिए कम से कम 3.25त्न वोट हासिल करना अनिवार्य होता है। यहां कसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है।

आज तक के इतिहास में यहां किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जिसके चलते गठबंधन की सरकार बनना ही यहां का मुख्य नियम रहा है। यही वजह है कि यहां बहुत कम ही ऐसी सरकारें रहीं जो अपना कार्यकाल पूरी की हो।

नेसेट में प्रवेश करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 3.25त्न वोट पाने अनिवार्य है। जिन पार्टियों को इतना वोट नहीं मिल पाता वो नेसेट नहीं पहुंच सकती। क्योंकि, उनके वोट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। उनकी कोई गिनती नहीं होती। इसके बाद बची हुई पार्टियों के बीच सीटों को उनके बचे हुए वोट शेयर के हिसाब से बांटा जाता है।

भारत और इजरायल की चुनाव प्रणाली में अंतर- इजरायल की चुनाव प्रणाली भारत की चुनाव प्रणाली की तुलना में बहुत अलग है। यहां भारत की तरह अलग-अलग लोकसभा या विधानसभा सीटें नहीं होतीं, बल्कि पूरा का पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है।

यहां मतदाता किसी स्थानीय नेता को व्यक्तिगत तौर पर वोट नहीं देते, बल्कि वे अपनी पसंद की पार्टी को वोट देते हैं। यहां किसी भी पार्टी को संसद में पहुंचने के लिए न्यूनतम 3.25त्न वोट हासिल करना अनिवार्य होता है। इस न्यूनतम सीमा को इलेक्टोरल थ्रेशोल्ड कहा जाता है।

संसद (नेसेट) की कुल 120 सीटों का बंटवारा पार्टियों को मिले राष्ट्रीय वोट प्रतिशत के अनुपात में होता है। यदि किसी पार्टी को 10त्न वोट मिलते हैं, तो उसे लगभग 12 सीटें मिलेंगी।

वहीं, भारत में मतदाता अपने क्षेत्र के किसी एक खास उम्मीदवार को वोट देते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वह जीत जाता है, भले ही उसे कुल मतों का 50त्न न मिला हो।

सऊदी अरब ने सेना के विमानों से हूती विद्रोहियों के पास पहुंचाए 1 अरब डॉलर, हमले रोकने की अपील



नई दिल्ली (एजेंसी)। इजरायली मीडिया ने खाड़ी क्षेत्र के राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब ने यमन के हूती समूह को 1 अरब डॉलर देने की पेशकेश की है। यह पेशकश ईरान की मध्यस्थता में हुई एक व्यवस्था के तहत की गई है जिसका मकसद युद्धविराम कराना और सऊदी अरब पर हो रहे हमलों को रोकना है।

सैन्य विमान से नकद ले जाने का दावा-रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान संभावित युद्धविराम पर बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ तेहरान पहुंचे थे। इस प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान के माध्यम से हूती समूह को 1 अरब डॉलर दिए जाने की योजना है।

राजनयिक सूत्रों ने दावा किया कि सऊदी मंत्री यह धनराशि हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान में लेकर तेहरान पहुंचे थे। हालांकि, सऊदी अरब के आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कोई रकम सीधे ट्रांसफर की गई है या नहीं।

तेहरान में आयोजित इस बैठक में कई प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के शीर्ष अधिकारी एक मेज पर नजर आए। खबरों के मुताबिक, इस बातचीत में तुर्किए के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलिन और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर शामिल हुए।

इनके साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के महासचिव मोहसेन रेजाई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (ढ्ढश्रस्ट) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

साथ ही सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान और मक्का संयुक्त रक्षा गठबंधन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह दौरा मक्का संयुक्त रक्षा गठबंधन के प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय तनाव को कम करना, बातचीत को बढ़ावा देना और कतर व पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मध्यस्थता प्रयासों को समर्थन देना है।

विवाद का कारण तीन साल पुराने समझौते की शर्त

इजरायली मीडिया से बात करते हुए सऊदी अधिकारी ने रकम ट्रांसफर होने की खबर की पुष्टि तो नहीं की लेकिन ये स्पष्ट किया कि विवाद का मुख्य कारण तीन साल पुराने समझौते की शर्त है।

पूर्व समझौतों के तहत सऊदी अरब को हूती समूह के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और नागरिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देनी थी, जिसके बदले में हूती विद्रोहियों को हमले पूरी तरह बंद करने थे।

हूती विद्रोहियों का आरोप है कि रियाद ने समझौते का पालन नहीं किया। वहीं सऊदी अरब का स्पष्ट रुख है कि वह किसी भी सैन्य ब्लैकमेल के दबाव में आकर युद्धविराम नहीं करेगा। रियाद की शर्त है कि फंडिंग तभी दी जाएगी जब हूती यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से छीने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वापस सौंपेंगे।

होर्मुज में तेल टैंकर पर हमले बने बातचीत की वजह रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल सुविधाओं पर बढ़ते हमलों के बीच ईरान ने सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की। इन हमलों की वजह से सऊदी अरब को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

18000 सैलरी और डीए का एलान, सरकार ने किसे दिया समान काम, समान वेतन का हक?



नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार कर करे हैं। उम्मीद है कि सरकार बुधवार, 28 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट दे सकती है। इस बीच दिल्ली सरकार ने अपने 4000 से ज्यादा कर्मचारियों को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बड़े फैसले की घोषणा की। जिसे तहत समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के तहत दिल्ली नगर निगम के करीब 4000 कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन अब बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी मिलेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वेतन संशोधन से सरकारी खजाने पर 52 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आएगा।

कर्मचारियों का बैकग्राउंड- ये वे कर्मचारी हैं जिन्हें पहले डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया गया था और बाद में इन्हें मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी पब्लिक हेल्थ के रूप में पदनाम दिया गया। स्ख्ष्ठ कमिश्नर संजीव खिरवार ने एक बयान में बताया कि इन कर्मचारियों ने वर्षों से घर-घर जाकर पब्लिक हेल्थ से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

नई व्यवस्था के तहत इनका वेतन पे मैट्रिक्स के लेवल-1 यानी 18,000 रुपए तय किया गया है, जिसमें वेरिएबल डीए भी शामिल है। मेयर प्रवेश वाही ने खुशी जताते हुए कहा कि बढ़ी हुई सैलरी सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि वेतन और डीए बढ़ाने का यह प्रस्ताव पिछले बजट में घोषित किया गया था, जिसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था।

क्या बोलीं ष्टरू रेखा गुप्ता- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम दशकों से पब्लिक हेल्थ में समर्पित भाव से काम कर रहे कर्मचारियों के योगदान को सच्ची मान्यता देता है। उन्होंने कहा, दिल्ली की सेवा करने वाले हजारों कर्मचारियों की देखभाल करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना हमारी सरकार का कर्तव्य है।

2,500 नए स्वच्छता कर्मचारियों की भर्ती

कर्मचारियों की भलाई से जुड़े इस कदम के साथ ही स्ख्ष्ठ ने शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी कमर कस ली है। त्योहारी सीजन और दिवाली के दौरान बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ को देखते हुए मेयर ने 2,500 नए स्वच्छता कर्मचारियों की भर्ती का भी एलान किया है।

मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि साफ-सफाई के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जमीन पर सुधार साफ तौर पर नजर आना चाहिए।

ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव हारते ही फ्लेवियो पर एक्शन



नई दिल्ली (एजेंसी)। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा से हार के बाद ब्राजील के सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो को 24 घंटे के अंदर अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है और उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। यह गोपनीय आदेश सुप्रीम फेडरल कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरेस द्वारा जारी किया गया है

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच जारी- ब्राजील की सरकारी समाचार एजेंसी एजेंसिया ब्रासिल की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई फेडरल पुलिस द्वारा मनी लॉन्ड्रिग और अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन की जांच के तहत की गई है। अदालत के आदेश के अनुसार, फ्लेवियो के सभी सामान्य और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद कर दिए गए हैं। इस आदेश के तहत बोल्सोनारो के वकील विलर टोमाज से संपर्क करने से भी मना किया है।

संक्षिप्त समाचार

भोपाल कमिश्नर का सख्त निर्देश : किसानों को खाद-बीज की नहीं होगी किल्लत, जनसमस्याओं का 50 दिन के भीतर करें समाधान



भोपाल। रबी सीजन 2026-27 के दौरान संभाग के किसानों को खाद, बीज और कृषि अनुदान हासिल करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए कृषि, सहकारिता और अन्य संबंधित विभाग आपसी तालमेल से काम करें। संभाग में खाद-बीज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। यह निर्देश संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने बुधवार को आयुक्त कार्यालय में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। संभागायुक्त ने कहा कि इस बार शासन ने खाद वितरण व्यवस्था को काफी सरल बना दिया है। किसान अब घर बैठे व्हाटसएप के जरिए टोकन जनरेट कर सकते हैं, साथ ही पंचायत स्तर पर फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को खाद लेने के लिए दूर न भटकना पड़े। उन्होंने किसानों को समय पर बुवाई करने की सलाह दी, ताकि मिट्टी की प्राकृतिक नमी का पूरा फायदा उठाया जा सके। इसके अलावा फसल विविधीकरण, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और प्रमाणित बीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।

सिंचाई के लिए मिले निर्बाध बिजली, नरवाई जलाने पर लगे रोक : बैठक में संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि रबी सीजन में सिंचाई के लिए किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए और अकारण कटौती बिल्कुल न हो। खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) का उपयोग अनिवार्य किया जाए। साथ ही, किसान बीमा योजना का लाभ अधिक दिलाया जाये।

रोजगार की दिशा में बड़ी पहल : अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में 'युवा संगम रोजगार मेला' आयोजित, 107 युवाओं का प्राथमिक चयन



भोपाल। जिला रोजगार कार्यालय, भोपाल के तत्वावधान में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय परिसर में युवा संगम रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना था। आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित क्षेत्रों की कुल 16 कंपनियों ने सहभागिता की। मेले में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अवसर पाने के लिए कुल 160 युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया। कंपनियों द्वारा आयोजित प्राथमिक साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया के उपरांत 107 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस प्रकार के आयोजन शिक्षित युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के अनुरूप करियर का मार्ग प्रशस्त करने में बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। मेले के माध्यम से न केवल युवाओं को रोजगार के सीधे अवसर मिले, बल्कि वे अपने भविष्य के करियर को लेकर भी प्रोत्साहित हुए।

नक्सल प्रभावित रहे बालाघाट के 100 गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रशासन ने तेज किए प्रयास

भोपाल। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित रहे 100 चिन्हित गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप संचालित इस अभियान के तहत गत 26 और 28 अक्टूबर को बैहर, बिरसा, लांजी और किरनापुर विकासखंड के गांवों में अधिकारियों ने पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं, स्थानीय समस्याओं और विकास की संभावनाओं की जानकारी जुटाई गई। ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और रोजगारमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। नक्सल प्रभावित रहे 100 गांवों को चार क्लस्टर में विभाजित कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भ्रमण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

TIT कॉलेज के छात्रों के विवाद में पिस्टल लेकर पहुंचा युवक, पुलिस जवान पर तान दी बंदूक

- एक सप्ताह पुरानी रंजिश में इंद्रपुरी चौराहे पर हंगामा,
- रेस्टोरेंट में मौजूद जवान ने रोकने की कोशिश की तो उसी पर तान दी पिस्टल, घटना सीसीटीवी में कैद

भोपाल (ब्यूरो)

भोपाल। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में TIT कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक सप्ताह पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए एक छात्र इंद्रपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में पिस्तौल लेकर पहुंच गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी युवक ने न केवल दूसरे छात्र को धमकाने की कोशिश की, बल्कि बीच-बचाव करने पहुंचे एक पुलिस जवान पर भी पिस्टल तान दी। पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले में पिपलानी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।



एक सप्ताह पुरानी रंजिश में इंद्रपुरी चौराहे पर हंगामा : जानकारी के मुताबिक, करीब एक सप्ताह पहले TIT कॉलेज के छात्र शिवांशु और पृथ्वीराज सिंह राजपूत के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पृथ्वीराज के साथियों ने शिवांशु के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव बना हुआ था। इसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के इरादे से पृथ्वीराज सिंह राजपूत अपने साथी राज राजपूत के साथ इंद्रपुरी चौराहे पर पहुंचा था। आरोप है कि राज राजपूत अपने साथ पिस्टल लेकर आया था और वहां पहुंचकर शिवांशु को धमकाने की कोशिश कर रहा था। अचानक हथियार लेकर युवक के पहुंचने से मौके पर अफरा-तफरी और तनाव की स्थिति बन गई।

पुलिस जवान पर ही तान दी पिस्टल

इसी दौरान वहां स्थित एक रेस्टोरेंट में मौजूद पुलिस जवान पंकज डेहरिया ने स्थिति को भांपते हुए युवक को रोकने और मामला संभालने का प्रयास किया। आरोप है कि जैसे ही पुलिस जवान ने हस्तक्षेप किया, आरोपी राज राजपूत ने उसी पर पिस्टल तान दी। एक छात्र के विवाद में इस तरह सीधे पुलिसकर्मी को ही हथियार के दम पर धमकाने की इस घटना ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

यह पूरी सनसनीखेज घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में आरोपी के हाथ में पिस्टल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज को घटना के घटनाक्रम की पुष्टि और साक्ष्य के रूप में बेहद अहम मानकर जांच कर रही है।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीमें

इस पूरे मामले पर एसीपी आदित्य बी सक्सेना ने बताया कि TIT कॉलेज के दो छात्र गुटों के बीच विवाद चल रहा था। पृथ्वीराज सिंह अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट पहुंचा था और उसके साथी के हाथ में पिस्टल थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया है। आरोपी के पकड़े जाने पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। फिलहाल, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

1 से 5 नवंबर तक सजेगा पश्चिम मध्य रेल की 9वीं राज्य स्काउट्स एवं गाइड्स रैली का मंच

भोपाल (ब्यूरो)

भोपाल। पश्चिम मध्य रेल भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा 9वीं राज्य स्तरीय रैली का भव्य आयोजन 1 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक रेलवे स्पोर्ट्स Ground, हबीबगंज रेलवे कॉलोनी, भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के इस प्रमुख वार्षिक आयोजन में मुख्यालय सहित भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडलों से लगभग 400 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स और यूनिट लीडर्स हिस्सा लेंगे।

पांच दिवसीय इस रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना, टीमवर्क और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे नैतिक मूल्यों का विकास करना है। रैली के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागी अपनी कला, रचनात्मकता, संगठनात्मक कौशल और शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन करेंगे।

आयोजन का मुख्य आकर्षण ग्रैंड कैंपफायर और समापन समारोह होगा, जो 4 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री दिलीप कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करेंगे। जनसंपर्क विभाग (पश्चिम मध्य रेल, भोपाल) के अनुसार, यह राज्य रैली रेल परिवार के युवाओं को एकजुट करने के साथ-साथ उनमें राष्ट्र सेवा और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूती देने का कार्य करेगी।

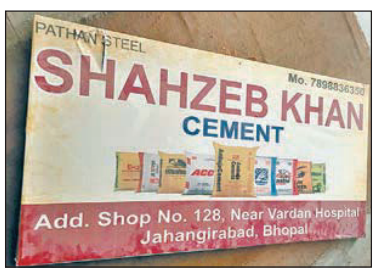
दुकान के कर्मचारियों ने मालिक को लगाया लाखों का चूना, फर्जी लोन लिया और माल बेचकर हुए फरार

भोपाल (ब्यूरो)

भोपाल। राजधानी के जहांगीराबाद इलाके में एक खौफनाक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लोहे और सीमेंट की दुकान चलाने वाले प्रोपराइटर की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए उनके ही दो कर्मचारियों ने दुकान पर फर्जी नाम से लोन ले लिया और दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान बेचकर फरार हो गए। पीड़ित दुकान मालिक ने इस संबंध में एसीपी (ACP) को लिखित शिकायत देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

क्या है पूरा मामला

शिकायतकर्ता फराहन खान की जहांगीराबाद क्षेत्र के वरदान अस्पताल बस स्टैंड के पास 'पठान स्टील' (शॉप नं. 128) के नाम से सरिया और सीमेंट की दुकान है। दुकान पर शाजेब खान उर्फ जेब और रिजवान खान वर्ष 2014 से काम कर रहे थे। शाजेब को 15,000/- रुपये मासिक वेतन पर रखा गया था, जबकि रिजवान को 500/- रुपये प्रतिदिन रोजनदारी पर काम पर रखा गया था।



मालिक के बाहर जाते ही रची साजिश

पीड़ित प्रोपराइटर फराहन मोहम्मद खान रिश्तेदार और पुराना परिचित होने के कारण अपने कर्मचारियों पर पूरा भरोसा करते थे। इसी भरोसे के चलते वे अपने किसी निजी काम से भोपाल से बाहर गए हुए थे। जब वे वापस लौटे और दुकान पर पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

जांच में पता चली कई बातें

फर्जी लोन लिया गया : आरोपियों ने दुकान पर फर्जी बोर्ड लगाकर कागजों में हेराफेरी की और लोन ले लिया, जिसकी कोई किश्त नहीं चुकाई गई है। अब बैंक और फाइनेंस कंपनियों के लोग दुकान के चक्कर काट रहे हैं।

लाखों का सामान बेचा : दुकान में रखा लगभग 8,00,000/- रुपये (आठ लाख रुपये) कीमत का लोहा और सीमेंट अन्य पार्टियों को बेचकर सारा पैसा आरोपी अपने खातों में समेट कर चंपत हो गए।

दुकान छोड़कर भागे : दोनों कर्मचारी दुकान को पूरी तरह सूना छोड़कर भाग चुके हैं।

पुलिस से न्याय की गुहार : पीड़ित दुकानदार ने एसीपी (ACP) कार्यालय में आवेदन देकर आरोपियों शाजेब खान और रिजवान खान के खिलाफ तत्काल धोखाधड़ी, गबन और फर्जीवाड़े का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ट्रेन में तेज आवाज में बजाया गाना या चलाई रील, तो लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना, हो सकती है छह महीने की जेल

भोपाल (ब्यूरो)

भोपाल। रेल यात्रा के दौरान यदि आप अपने मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने सुनते हैं, रील देखते हैं या स्पीकर पर वीडियो चलाते हैं, तो यह आदत अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने



या शांति भंग करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर 1,000 तक का जुर्माना, 6 जिम्मेदारी है। उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे ऑडियो-वीडियो सामग्री देखते या सुनते समय ईयरफोन का उपयोग करें।

रात के समय और AC कोचों के लिए विशेष निर्देश : रेलवे ने विशेष रूप से रात के समय और वातानुकूलित (AC) कोचों में यात्रा कर रहे

उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर हो अस्पतालों में भर्ती : शुक्ल

ई-संजीवनी का प्रभावी उपयोग कर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श की उपलब्धता बढ़ाएं

भोपाल (ब्यूरो)

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, उपलब्धता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इन सेवाओं की प्रगति, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान, फॉलोअप एवं समय पर संस्थागत भर्ती की नियमित समीक्षा की जाएग। सभी स्तरों पर अधिकारियों एवं मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही निर्धारित कर अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन एवं निर्धारित प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री



ई-संजीवनी से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श की उपलब्धता बढ़ाएं

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए आमजन को सेवा के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपयोगिता के प्रति विश्वास विकसित करना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल कहा कि भारत में तकनीक को अपनाने की व्यापक क्षमता का प्रत्यक्ष उदाहरण यूपीआई है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का प्रभावी उपयोग कर नागरिकों को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

लिया जाए। बताया गया कि वर्तमान में चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से लगभग 30 प्रतिशत ही पर्याप्त समय पूर्व स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती हो पा रही हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विशेष कार्ययोजना के अनुरूप समन्वित

अनमोल पोर्टल एवं सुमन कमांड सेंटर से होगी प्रभावी निगरानी : समीक्षा में बताया गया कि अनमोल पोर्टल पर लगभग 6.2 लाख गर्भवती महिलाओं का विवरण दर्ज है, जिनमें लगभग 2 लाख महिलाओं को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के रूप में चिन्हित किया गया

मुख्य सचिव बर्णवाल ने की आर्मी डे परेड की तैयारियों की समीक्षा

भोपाल (ब्यूरो)

भोपाल। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने आगामी 15 जनवरी को भोपाल में आर्मी डे परेड के मुख्य आयोजन और इससे पूर्व होने वाले अन्य कार्यक्रमों को शौर्य और गौरवपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी संबंधित विभाग को उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों के साथ आयोजन स्थलों की व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, आवास, प्रोटोकॉल एवं प्रचार-प्रसार आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की तथा अब तक की गयी तैयारी की जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह संजय कुमार शुक्ला एवं सामान्य प्रशासन शिवशेखर



शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव बर्णवाल ने निर्देश दिए कि आर्मी डे परेड के मुख्य आयोजन के लिए भेल स्थित कालीबाड़ी मार्ग पुनरूद्धार और रिसर्फेसिंग सहित विद्युत लाइनों के शिफ्टिंग की कार्रवाई तय समय-सीमा में कर ली जाए। लोक निर्माण विभाग ने आश्वस्त किया कि ये सभी कार्य आगामी 1 दिसंबर तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि मुख्य आयोजन के लिए अतिविशिष्ट, विशिष्ट अतिथियों 45 हजार दर्शकों के लिए व्यवस्थाएं किए जाने की योजना बनाकर लोनिवि, नगर निगम, जिला प्रशासन समन्वय से कार्य प्रारम्भ किया गया है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और एयर-शो : टी.टी नगर स्टेडियम में शौर्य संस्कृति कार्यक्रम तथा भोपाल अपर लेक में होने वाले एयर शो के लिए भी सेना के अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्य सचिव बर्णवाल ने निर्देश दिए कि उक्त कार्यक्रमों में यातायात, पार्किंग, प्रवेश, निकास एवं समग्र सुरक्षा व्यवस्था की कार्य-योजना तैयार कर पुलिस आयुक्त भोपाल और ट्रैफिक पुलिस प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

रिहर्सल के दौरान सुविधाजनक वैकल्पिक मार्ग हों

मुख्य सचिव बर्णवाल ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर एक दिसम्बर से प्रारंभ होने वाली रिहर्सल के चलते नागरिकों और वाहनों आदि के लिए आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्गों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मार्गों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे नागरिकों को असुविधा न हों। उन्होंने निर्देश दिए कि वैकल्पिक मार्गों का सुधार कार्य करें और आवश्यक संकेत लगाएं, जिससे नागरिकों को बिल्कुल भी असुविधा नहीं हो। बर्णवाल ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश के कार्यों की बेहतर ब्रांडिंग के साथ ही सिहंस्थ और प्रदेश के सांची, खजुराहो, भीमबेटका, ओरछा सहित पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रदर्शन किया जाए।

सुबह छह बजे सड़कों पर उतरे निगम आयुक्त कहा-

दुकानों के बाहर सामान मिला तो खैर नहीं

भोपाल (ब्यूरो)

सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण, धूल-मिट्टी और गंदगी को लेकर नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार सुबह 6 बजे उन्होंने कोलार क्षेत्र का निरीक्षण कर दुकानों के बाहर फैले सामान को हटाने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोलार रोड, स्वर्ण जयंती पार्क, सर्वधर्म, दानिश कुंज और संस्कार उपवन सहित विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया। आयुक्त ने दुकानों के बाहर सामान व्यवस्थित रखने, प्लास्टिक-पन्नी हटाने और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखने को कहा। सब्जी विक्रेताओं को ठेलों पर डस्टबिन रखने की हिदायत देने के निर्देश भी दिए, ताकि बाजारों में कचरा न फैले।



चौराहों की बदलेगी सूरत

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सफाई केवल झाड़ू लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि शहर की सुंदरता भी नजर आनी चाहिए। उन्होंने चौराहों और सड़क विभाजकों से धूल-मिट्टी व घासफूस हटाकर पौधे लगाने, गमले रखने और नियमित पानी का छिड़काव कराने को कहा। दानिश कुंज तिराहे पर रंगाई-पुताई और फव्वारों को बेहतर ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। स्वर्ण जयंती पार्क को जनभागीदारी से विकसित करने और संस्कार उपवन के आसपास सफाई सुधारने पर भी जोर दिया। निरीक्षण में निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।





स्वात्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक , प्रकाशक **साहबजादा अब्दुल रशीद खान** द्वारा आर.के. एण्ड प्रिंटर्स 7 नीम वाली सड़क जिंसी जहांगीराबाद भोपाल म.प्र.482008 से मुद्रित तथा 424, मेहंदी वालीगली, तलैया भोपाल म.प्र. 462001 से प्रकाशित।
सम्पादक- अज़रा बैगम (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल न्यायालय रहेगा।) RNI No. MPHIN/2021/82412